राष्ट्रीय छात्रशक्ति

वर्ष-48 ■ अंक-02 ■ मई 2026 ■ ₹10 ■ पृष्ठ-40

सांस्कृतिक उन्मेष

अभिवाचन कार्यक्रम की झलकियां

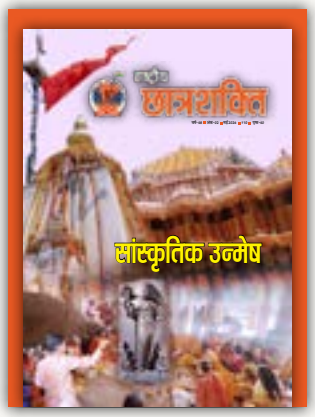

राष्ट्रीय
छात्रशक्ति

शिक्षा क्षेत्र की प्रतिनिधि पत्रिका

वर्ष-48, अंक-02
मई 2026

संपादक
आशुतोष भटनागर
संपादक मण्डल
संजीव कुमार सिन्हा
अवनीश सिंह
अभिषेक रंजन
अजीत कुमार सिंह

संपादकीय पत्राचार
राष्ट्रीय छात्रशक्ति
26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,
नई दिल्ली - 110002.
फोन : 011-23216298
www.chhatrashakti.in
rashtriyachhatrashakti@gmail.com
www.facebook.com/Rchhatrashakti
www.twitter.com/Rchhatrashakti
www.instagram.com/ Rchhatrashakti

स्वामी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक **राजकुमार शर्मा** द्वारा 26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, आई.टी.ओ. के निकट, नई दिल्ली - 110002 से प्रकाशित एवं ओशियन ट्रेडिंग कं., 132 एफ. आई. ई., पटपड़गंज इण्डस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली-110092 से मुद्रित। **संपादक** *पीआरबी अधिनियम के तहत समाचारों के चयन के लिए जिम्मेवार।

अबकी बार

05 **भारतीयता का प्रचंड शंखनाद**

भारत की सांस्कृतिक परंपरा में कुछ स्थल केवल स्थापत्य या धार्मिक केंद्र नहीं होते, वह राष्ट्र...

संपादकीय	04
हिंदू अस्मिता के पुनर्निर्माण का प्रतीक सोमनाथ मंदिर	09
बंग-विजय का निहितार्थ	12
विकासोन्मुखी जनभावनाओं का परिचायक हैं चुनाव परिणामः अभाविप	15
Bharat's Vision for Responsible Artificial Intelligence	16
शैक्षणिक एवं बुनियादी ढांचे से जुड़े सुधारों की मांग	17
सिएटल में लगी स्वामी विवेकानंद की पहली प्रतिमा	18
वंदे मातरम के अपमान पर सजा का प्रावधान	18
एनटीए मुख्यालय पर अभाविप का धरना-प्रदर्शन	19
पर्यावरण संरक्षण पर मंथन	20
विभिन्न मांगों को लेकर अभाविप का प्रदर्शन	22
नेतृत्व विकास का सशक्त माध्यम बनी छात्रा संसद	23
परमाणु क्षेत्र में बढ़ता स्वदेशीकरण	24
सुरक्षा एवं रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है ग्रेट निकोबार परियोजना	25
समाज को दिशा प्रदान करती है कला	28
National Symposium Highlights One Health Approach for Rural Resilience	30
एनसीईआरटी को मिला 'डीम्ड विश्वविद्यालय' का दर्जा	32
अमर्यादित शिक्षक के विरुद्ध कार्रवाई का अभाविप ने किया स्वागत	32
'शाश्वत है प्रा.केलकर प्रदत्त कार्यपद्धति'	33
संघर्ष, स्वतंत्रता और विकास की गाथा के दो सौ वर्ष	35
साधारण से असाधारण बनने की यात्रा	37

वैधानिक सूचना : राष्ट्रीय छात्रशक्ति में प्रकाशित लेख एवं विचार तथा रचनाओं में व्यक्त दृष्टिकोण संबंधित लेखकों के हैं। संपादक, प्रकाशक एवं मुद्रक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। समस्त प्रकार के विवादों का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा।

संपादकीय

यह माह भारत के सांस्कृतिक उन्मेष के अवसर के रूप में पहचाना जाएगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) जिस 'वाग्देवी' की उपासक है, उसके मध्य प्रदेश के भोजशाला स्थित एक हजार वर्ष पुराने मंदिर के पुनर्निर्माण का मार्ग प्रशस्त होता दिखाई दे रहा है। 1035 में वसंत पंचमी के दिन वाग्देवी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा तत्कालीन राजा भोजदेव द्वारा की गई। चौदहवीं सदी के प्रारंभ में मंदिर को आक्रांताओं द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। उसके बाद से ही स्थानीय समाज निरंतर आंदोलित था, जिसे राष्ट्रव्यापी समर्थन प्राप्त था।

स्वतंत्रता के बाद भी यह संघर्ष जारी रहा, जिसकी अंतिम परिणति न्यायालय के माध्यम से सभी के सामने है। यद्यपि दूसरा पक्ष उच्चतम न्यायालय जाएगा ही, किन्तु तथ्यों पर उच्च न्यायालय में ही विस्तृत चर्चा हो चुकी है, जिसके चलते यह संभावना कम ही है कि निर्णय बदलने की स्थिति आएगी। मां वाग्देवी की मूल प्रतिमा जो आज लंदन में है, को भी भारत लाने के प्रयास जारी हैं।

सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भी उसके ध्वंस के लगभग एक हजार वर्ष बाद हुआ। तत्कालीन राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसाद, गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी के प्रयासों से यह कार्य सम्पन्न हुआ। यद्यपि तब भी अनावश्यक बाधाएं उत्पन्न करने की कोशिशें हुई थीं, किन्तु सफल नहीं हो सकीं। इस ऐतिहासिक घटना के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें स्वयं प्रधानमंत्री उपस्थित रहे।

1035 में वसंत पंचमी के दिन वाग्देवी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा तत्कालीन राजा भोजदेव द्वारा की गई। चौदहवीं सदी के प्रारंभ में मंदिर को आक्रांताओं द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। उसके बाद से ही स्थानीय समाज निरंतर आंदोलित था, जिसे राष्ट्रव्यापी समर्थन मिला।

स्वतंत्रता आंदोलन में भारत की चेतना को जगाने वाले राष्ट्रगीत 'वन्दे मातरम' को अनिवार्य बनाया जाना भी अभाविप कार्यकर्ताओं के लिए आत्मिक संतोष का विषय है। बंकिमचन्द्र द्वारा रचित यह गीत सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि में लिखे गए उनके उपन्यास 'आनंदमठ' में समाहित किया गया था। बंग-भंग के समय यह गीत क्रांति के स्वर के रूप में स्थापित हुआ तथा आगे चल कर देश के बलिदानी क्रांतिकारियों के लिए गीत मंत्ररूप बन गया। स्वतंत्र भारत में भी यह निरंतर प्रेरणा दे रहा है।

पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम स्वयं में इस बात की घोषणा है कि राज्य के मतदाताओं में इस बार सांस्कृतिक पहचान को चुना है। दशकों से समाज की आस्था और मान्यताओं पर लगातार होने वाली चोट से मतदाताओं का धैर्य चुक गया और उन्होंने अप्रत्याशित बहुमत देकर स्थापित राजनीतिक दुरभिसंधि को नकार दिया। यही स्थिति असम चुनाव में रही। दोनों ही राज्य प्रायः समान चुनौतियों से जूझ रहे हैं। पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु की सरकारें केन्द्र के प्रति अंध-विरोध के कारण किसी भी केन्द्रीय कल्याणकारी योजनाओं को लागू नहीं कर रही थीं, जिसका परिणाम राज्य के शेष देश से अलग-थलग पड़ने के रूप में दिखाई देने लगा था। इन राज्यों के मतदाताओं ने अलगाव वाली राजनीति को नकार कर देश की विकास यात्रा में सहयात्री होने का जनादेश दिया है।

सांस्कृतिक भारत का भौगोलिक परिचय हिमालय से हिन्द महासागर तक कह कर दिया जाता है। यह अभूतपूर्व था कि एक ओर दक्षिण में तमिलनाडु में मंत्रिमण्डल के शपथग्रहण समारोह का प्रारंभ विभाजनकारी राजनेताओं के विरोध के बावजूद 'वन्दे मातरम्' से हुआ, वहीं दूसरी ओर सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के महिला दल ने 'एवरेस्ट' के शिखर पर तिरंगा फहराया। वह 3 मिनट 52 सेकेंड इतिहास में सदैव के लिए अमिट अक्षरों में लिख दिए गए, जब बल की महिला पर्वतारोहियों ने 'सागरमाथा' (माउंट एवरेस्ट अथवा गौरीशंकर) पर राष्ट्रध्वज फहराने के बाद राष्ट्रगीत वन्दे मातरम् का गान किया।

विविध समाचारों तथा नियमित स्तंभों के साथ यह अंक आपके समक्ष प्रस्तुत है।

आपका
संपादक

भारतीयता का प्रचंड शंखनाद

■ अजीत कुमार सिंह

भारत की सांस्कृतिक परंपरा में कुछ स्थल केवल स्थापत्य या धार्मिक केंद्र नहीं होते, वह राष्ट्र की आत्मा और सभ्यता की स्मृति के प्रतीक बन जाते हैं। मध्यप्रदेश में धार स्थित मां वाग्देवी का मंदिर भोजशाला ऐसा ही ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक केंद्र है, जिसका नाम भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत साधना, विद्या-अर्चना और सांस्कृतिक अस्मिता के साथ जुड़ा हुआ है। भोजशाला का इतिहास केवल एक मंदिर का इतिहास नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता की उस गौरवगाथा का परिचायक है, जहां शिक्षा, संस्कृति, धर्म और राष्ट्रीय चेतना का अद्वितीय समन्वय दिखाई देता है।

राजा भोज और भोजशाला की स्थापना

परमार वंश के शासक राजा भोज भारतीय इतिहास में केवल एक वीर और कुशल प्रशासक के रूप में ही नहीं, बल्कि विद्या, साहित्य, दर्शन, वास्तु, चिकित्सा और संस्कृति के महान संरक्षक के रूप में भी स्मरण किए जाते हैं। इतिहास बताता है कि राजा भोज स्वयं मां सरस्वती के अनन्य उपासक थे और 1034 में उन्होंने मां सरस्वती की आराधना तथा संस्कृत एवं भारतीय ज्ञान परंपरा के संरक्षण एवं प्रसार के उद्देश्य से भोजशाला का निर्माण कराया।

भोजशाला का परिसर अत्यंत विशाल और स्थापत्य की दृष्टि से उत्कृष्ट माना जाता है। यह पूर्वमुखी बहुमंजिला आयताकार भवन था, जिसका विस्तार ज्ञानपुरा क्षेत्र तक फैला था। तत्कालीन समय में ज्ञानपुरा आचार्यों और विद्वानों का निवास क्षेत्र था। यहां देश-विदेश से विद्यार्थी और विद्वान अध्ययन एवं साधना के लिए आते थे। इस प्रकार भोजशाला भारतीय शिक्षा परंपरा का एक प्रमुख केंद्र बन गया।

वाग्देवी की प्रतिमा और सांस्कृतिक गौरव

राजा भोज की आज्ञा से 1034 में प्रसिद्ध मूर्तिकार मनथल ने संगमरमर पर मां वाग्देवी (सरस्वती) की अत्यंत सुंदर एवं अद्वितीय प्रतिमा का निर्माण किया। 1035 में वसंत पंचमी के अवसर पर 40 दिवसीय भव्य महोत्सव आयोजित किया गया, जिसमें हजारों संत,

विद्वान और धर्माचार्य उपस्थित रहे। महोत्सव में महायज्ञ के साथ वाग्देवी प्रतिमा की प्राण-प्रतिष्ठा की गई। इस आयोजन के बाद भोजशाला अखिल भारतीय सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र के रूप में स्थापित हुई। भोजशाला की सांस्कृतिक प्रतिष्ठा का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि 1960 में भारतीय साहित्य के सर्वोच्च सम्मान 'ज्ञानपीठ पुरस्कार' का प्रतीक-चिह्न भी भोजशाला की वाग्देवी प्रतिमा से प्रेरित होकर बनाया गया।

भोजशाला केवल धार्मिक साधना का केंद्र नहीं, बल्कि भारतीय ज्ञान-विज्ञान की महत्वपूर्ण प्रयोगशाला भी बनी। राजा भोज स्वयं महान विद्वान और ग्रंथकार थे। उन्होंने साहित्य, ज्योतिष, आयुर्वेद, राजनीति, धर्मशास्त्र, व्याकरण, वास्तु, विज्ञान, दर्शन और शिल्प जैसे विषयों पर लगभग 84 ग्रंथों की रचना की। रामायण पर आधारित अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ 'चम्पू रामायण' सहित 'सरस्वती कण्ठाभरण', 'राजमार्तण्ड' सहित अन्य प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना भी ज्ञान के इसी केंद्र में हुई। काशी के प्रसिद्ध विद्वान भाव बृहस्पति सहित अनेक आचार्यों ने भोजशाला में ही अध्ययन और साधना की, जिससे यह स्थान भारतीय दार्शनिक और सांस्कृतिक विमर्श का एक राष्ट्रीय केंद्र बन गया।

आक्रमण और संघर्ष का काल

मां सरस्वती का पावन मंदिर भोजशाला, जो अपने आंगन में धर्म-दर्शन के शास्त्रार्थों के लिए प्रसिद्ध था, जहां वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी, वह स्थान मुस्लिम आक्रांताओं की निगाह में चढ़ गया। 1305 में मुस्लिम आक्रांता अलाउद्दीन खिलजी ने परमारों के अभेद्य गढ़ मालवा पर बर्बर हमला किया और मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के साथ ही भोजशाला सहित अनेक हिन्दू मानबिन्दुओं को ध्वस्त कर दिया।

मालवा में परमार वंश के पतन और मुस्लिम सत्ता के विस्तार के साथ भोजशाला का संघर्षपूर्ण इतिहास प्रारंभ होता है। 1269 के लगभग कमालुद्दीन मालवी, जिसे कमाल मौला के नाम से जाना जाता था, ने स्वांग रचकर मालवा क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाया। इसके बाद ही मालवा क्षेत्र की राजनीतिक परिस्थितियां बदलीं और अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमणों का मार्ग प्रशस्त हुआ।

1305 में जिस समय अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा पर आक्रमण किया, उस समय परमार वंश के अंतिम राजा महलकदेव और सेनापति वीर गोगादेव ने भोजशाला की रक्षा के लिए वीरतापूर्वक संघर्ष किया। उन्होंने अपने जीवन

की अंतिम सांस तक भोजशाला को बचाने का प्रयास किया और युद्धभूमि में वीरगति प्राप्त की। संघर्ष के बाद भोजशाला के कुछ हिस्सों को ध्वस्त कर दिया गया, जिसका अनेक विद्वानों और आचार्यों ने प्रतिरोध किया। इतिहास बताता है कि लगभग 1200 विद्वानों को बंदी बनाकर मत परिवर्तन का दबाव बनाया गया, किंतु उन्होंने अपने धर्म और परंपरा को त्यागना स्वीकार नहीं किया।

मंदिर से मस्जिद बनाने के प्रयास

मालवा का सूबेदार बनाए जाने के बाद 1401 में दिलावर खां गोरी ने भोजशाला के कुछ हिस्सों को मस्जिद का स्वरूप देने का प्रयास किया और फिर 1514 में महमूद शाह खिलजी द्वितीय के कार्यकाल में भोजशाला को खंडित कर उसके बाहर कमाल मौला का मकबरा निर्मित करा दिया गया। उसके बाद से भोजशाला को 'कमाल मौला मस्जिद' सिद्ध करने के लगातार प्रयास प्रारंभ हुए, जो समय परिवर्तन के साथ धार्मिक और राजनीतिक विवाद का स्वरूप ग्रहण करता चला गया।

मराठा और अंग्रेजी शासन

मराठों ने 1703 में मालवा क्षेत्र में हिन्दू शासन स्थापित किया। इसके बाद भोजशाला पुनः हिन्दू सांस्कृतिक स्मृति का केंद्र बनी। लेकिन 1826 में यह क्षेत्र ईस्ट इंडिया कम्पनी के अधीन चला गया। अंग्रेजों ने 1904 में भोजशाला की ऐतिहासिक और स्थापत्य महत्ता को देखते हुए इसे संरक्षित स्मारक घोषित किया और 1962 में इसे भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन कर दिया गया।

स्वाधीनता के बाद का संघर्ष

स्वतंत्रता के बाद भोजशाला को लेकर विवाद पुनः उभरने लगे। 1930 में यहां पहली बार अनाधिकृत रूप से नमाज पढ़ने का प्रयास किया गया, जिसका हिन्दू संगठनों ने विरोध किया। 1962 में मुस्लिम समाज ने न्यायालय में दावा किया कि भोजशाला मस्जिद है और वहां लंबे समय से नमाज होती रही है। किंतु केंद्र सरकार, राज्य पुरातत्व विभाग तथा तत्कालीन मुख्यमंत्री कैलाशनाथ काटजू ने इन दावों को स्वीकार नहीं किया।

स्वाधीनता के पश्चात् 1952 में 'श्री महाराजा भोज स्मृति वसंतोत्सव समिति' का गठन हुआ। समिति ने सांस्कृतिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों के माध्यम से जनजागरण आरम्भ किया। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुरातत्ववेत्ता, साहित्यकार, इतिहासकार एवं पद्मश्री से सम्मानित डा. विष्णु श्रीधर वाकणकर ने 1961 में लंदन जाकर सरस्वती प्रतिमा का अध्ययन करके प्रमाणित किया कि यह वही प्रतिमा है, जिसे राजा भोज ने भोजशाला में प्रतिष्ठित किया था। उन्होंने लंदन संग्रहालय के अधिकारियों से प्रतिमा की वापसी के लिए विचार -विमर्श किया और भारत आने के बाद उन्होंने पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से और फिर 1977 में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से मुलाकात करके उन्हें भोजशाला की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्ता से अवगत कराया। लेकिन दुर्भाग्य से दोनों ही पूर्व प्रधानमंत्रियों ने इस विषय पर ध्यान ही नहीं दिया।

1990 के दशक का आंदोलन

1994 में धार नगरी के सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं स्वयंसेवकों द्वारा भोजशाला में मां सरस्वती वंदना और हनुमान चालीसा पाठ प्रारम्भ किया गया तथा भोजशाला मुक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ।

12 मई 1997 के पहले हिन्दुओं को भोजशाला में प्रवेश की अनुमति थी, किन्तु पूजा-अर्चना प्रतिबंधित थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मुस्लिम समुदाय को प्रत्येक शुक्रवार नमाज पढ़ने की अनुमति दी, जबकि हिन्दुओं के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाकर केवल वसंत पंचमी पर सशर्त प्रवेश की अनुमति दी गई। इस निर्णय से हिन्दू समाज में व्यापक आक्रोश फैल गया और हिन्दुओं ने बंद, धरना, प्रदर्शन, आंदोलन और ज्ञापनों के माध्यम से विरोध प्रकट किया। प्रत्येक मंगलवार भोजशाला के बाहर हनुमान चालीसा पाठ प्रारम्भ हुआ।

जनांदोलन

वर्ष 2000 में वसंत पंचमी के अवसर पर भोजशाला में मां सरस्वती यज्ञ एवं महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालु सम्मिलित हुए। यह सिलसिला आगामी वर्षों में भी जारी रहा।

बढ़ते जनसमर्थन को देखते हुए मुस्लिम समुदाय वसंत पंचमी के दिन कमाल मौलाना के 'यौम-ए-पैदाइश (जन्मदिवस)' के नाम पर नमाज, कव्वाली और लंगर का आयोजन करने लगा। इसके बाद प्रशासन ने पूजा-अर्चना पर कई शर्तें लगा दीं। इसके बावजूद श्रद्धालु हवन-पूजन के लिए आगे बढ़े। महिलाओं द्वारा यज्ञ में पति के साथ पूजा में बैठने के आग्रह पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, लेकिन श्रद्धालुओं ने यज्ञ एवं महाआरती सम्पन्न की। 2003 में होने वाले वसंत पंचमी पूजन तक भोजशाला

को प्रतिबंधों से मुक्त कराने के संकल्प के साथ व्यापक जनजागरण अभियान के साथ ही 'धर्मजागरण भोजरथ यात्रा' निकली। प्रशासन ने यात्रा रोकने का प्रयास किया, किन्तु जनसमर्थन के कारण असफल रहा।

ऐतिहासिक मोड़ बना 2003 का संघर्ष

6 फरवरी 2003 के दिन वसंत पंचमी के अवसर पर देश भर से हजारों श्रद्धालु भोजशाला पहुंच गए, जहां महामंडलेश्वर गिरिजानंद महाराज द्वारा सरस्वती पूजन एवं महायज्ञ प्रारम्भ किया गया। तत्कालीन केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जगमोहन ने 13 फरवरी 2003 को भोजशाला खोलने संबंधी एक पत्र मुख्यमंत्री को भेजा, किन्तु राज्य सरकार ने इसे अस्वीकार कर भोजशाला को कमाल मौलाना की मस्जिद घोषित कर दिया। इसके बाद 18 और 19 फरवरी 2003 को प्रशासन ने धारा-144 घोषित करके गिरफ्तारियां शुरू कर दी। लेकिन उत्साह के साथ हजारों श्रद्धालुओं ने भोजशाला की ओर कूच किया, जिन पर लाठीचार्ज, आंसू गैस और गोली चलाई गई, जिसके कारण दो लोगों की मृत्यु हो गई। प्रशासन ने सैकड़ों लोगों पर करोड़ों रुपए का सामूहिक जुर्माना भी लगाया।

लगातार आंदोलन के परिणामस्वरूप 8 अप्रैल 2003 को लगभग 698 वर्ष बाद भोजशाला में प्रतिदिन दर्शन एवं प्रत्येक मंगलवार अक्षत-पुष्प लेकर जाने की सशर्त अनुमति प्रदान की गई। इसके बाद भी यह आंदोलन भोजशाला की पूर्ण मुक्ति एवं गौरव की पुनर्स्थापना के लिए निरंतर जारी रहा।

उच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय

भोजशाला में मां सरस्वती के मंदिर में पूजा एवं धार्मिक स्वरूप निर्धारित करने के लिए 2022 में रंजना अग्निहोत्री सहित अन्य याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करके हिंदुओं को नियमित पूजा का अधिकार देने के साथ ही नमाज पर पूरी तरह रोक लगाने एवं लन्दन से मां वाग्देवी की मूल प्रतिमा को वापस भारत लाने की मांग की थी। याचिका पर उच्च न्यायालय ने मार्च 2024 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से रिपोर्ट मांगी और फिर एएसआई की ओर से अतिरिक्त महानिदेशक डा. आलोक त्रिपाठी सहित पचास पुरातत्वविदों, भाषा विज्ञानियों ने भोजशाला का सर्वेक्षण कार्य आरम्भ किया। मार्च 2024 से लेकर जुलाई 2024 तक लगातार 98 दिनों तक भोजशाला के वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने के बाद एएसआई ने 2,190 पृष्ठों वाली अपनी रिपोर्ट उच्च न्यायालय को सौंपी। रिपोर्ट में बताया गया कि भोजशाला में वर्तमान स्मारक के नीचे 11वीं 12वीं और 13वीं शताब्दी की टूटी हुईं मूर्तियां, मंदिर एवं प्राकृत और संस्कृत लिपि वाले अभिलेखों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। स्मारक की दीवारों पर मंदिर के अवशेष एवं खंडित हिन्दू मूर्तियां भी मिली। रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया गया कि यहां पहले कोई हिन्दू निर्माण था, जिसे तोड़कर उसके अवशेष वर्तमान निर्माण में उपयोग किए गए थे।

इसके बाद 15 मई 2026 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने भोजशाला मामले में महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक निर्णय सुनाया। निर्णय में धार स्थित भोजशाला को मां सरस्वती (वाग्देवी-वाणी की देवी) का प्राचीन मंदिर घोषित कर दिया। लगातार 24 दिनों तक नियमित सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के उस आदेश को भी निरस्त कर दिया, जिसमें शुक्रवार के दिन मुस्लिमों को भोजशाला में नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी।

खंडपीठ ने पांच याचिकाओं पर गत 15 मई को दिए अपने निर्णय में भोजशाला को मां सरस्वती का प्राचीन मंदिर घोषित करते हुए केंद्र सरकार और एएसआई को निर्देश दिया कि वह भोजशाला परिसर के प्रबंधन की रूपरेखा तैयार करें। भोजशाला की पूरी संपत्ति का प्रशासनिक नियंत्रण अब एएसआई के पास रहेगा। भोजशाला को दशकों से कथित कमाल मौला मस्जिद बताने वाले मुस्लिम पक्ष को न्यायालय ने नई मस्जिद के निर्माण के लिए राज्य सरकार से वैकल्पिक भूमि आवंटित करने की मांग करने का विकल्प दिया है।

उच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय के बाद एएसआई ने भोजशाला को लेकर नया प्रशासनिक आदेश जारी कर दिया है, जिसमें हिंदू समाज को भोजशाला परिसर में पूजा-अर्चना और अध्ययन संबंधी गतिविधियों के लिए निर्बाध प्रवेश देने की अनुमति दी गई है। न्यायालय का यह निर्णय केवल एक विवाद का अंत नहीं, बल्कि भारतीय सांस्कृतिक अस्मिता की पुनर्पुष्टि है। यह निर्णय आगामी पीढ़ियों को संदेश देता है कि इतिहास चाहे कितना भी धुंधला क्यों न बना दिया जाए, अंततः सत्य प्रमाणों के आधार पर ही सामने आता है। ■

हिंदू अस्मिता के प्रतीक सोमनाथ मंदिर
पुनर्निर्माण का अमृत महोत्सव

■ डा. रवि रमेशचंद्र शुक्ल

सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर गत 11 मई को 'सोमनाथ अमृत पर्व-2026' का आयोजन किया गया। इतिहास के झरोखे में झांकने पर इसका इतिहास मूलतः हिंदू अस्तित्व और अस्मिता का इतिहास के रूप में मिलता है। 11 मई 1951 को सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण पूरा हुआ, जिसकी प्राण-प्रतिष्ठा तत्कालीन राष्ट्रपति डा. राजेंद्र प्रसाद द्वारा हुई। सोमनाथ मंदिर का निर्माण चंद्रदेव ने किया था, जिसे बारह ज्योतिर्लिंगों में प्रथम माना जाता है। इसकी प्राण-प्रतिष्ठा श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को वैवस्वत मन्वंतर के दसवें त्रेता युग में हुई थी।

सोमनाथ मंदिर की अस्मिता पर सबसे भीषण आक्रमण 6 जनवरी 1026 को गजनी के धर्मांध और पाशविक रक्तपिपासु लुटेरे महमूद गजनवी ने किया था। इतिहासकार मिन्हाज उर सिराज जुझनी ने अपनी पुस्तक 'तबाकते-ए-नासीरी' (1260) में लिखा है, 'महमूद ने मूर्ति के चार टुकड़े किए थे, एक गजनी की जमीं मस्जिद में, दूसरा शाही महल की सीढ़ियों पर, तीसरा मक्का और चौथा मदीना भेज दिया'। एच. एम. इलियट के अनुसार, 'उसने (महमूद) भारत के विरुद्ध धार्मिक युद्ध (जेहाद) छेड़ दिया था। उसे लगता था कि हिंदुओं को मुसलमान बना दिया जाएगा। भारतीयों ने भी उसका कड़ा प्रतिरोध किया। राजा भीमदेव और पचास हजार हिंदुओं का रक्तपात करके मुस्लिम आक्रमण के इतिहास का एक बड़ा हिंदू नरसंहार किया गया था।

कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने अपनी पुस्तक 'सोमनाथ द श्राइन' में महमूद की धर्मांधता और हिंदू

घृणा का उल्लेख किया है। महमूद ने मूर्तियों को गलियों और मस्जिद की सीढ़ियों पर डलवा दिया, जिससे नमाज के लिए जाने वाले मुसलमान उन्हें अपने पैरों से रौंद सकें। इस मूर्ति की गिनती संसार की महान आश्चर्यजनक वस्तुओं में की जाती थी। वह मंदिर के बीच में (गर्भगृह) में स्थित थी और नीचे अथवा ऊपर बिना किसी सहारे के टिकी हुई थी। हालांकि राजा परमदेव के खदेड़ने के बाद गजनी भाग गया और फिर भारत नहीं आया।

पटेल की प्रतिज्ञा, नेहरू का विरोध और पुनर्निर्माण

नानजी कालिदास मेहता को 21 नवंबर 1948 को लिखे पत्र में सरदार पटेल मंदिर निर्माण के लिए सार्वजनिक सहयोग की बात करते हैं। अपने लेख 'ग्रेट पॉवर' में

सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण और उद्घाटन में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का जवाहरलाल नेहरू ने एड़ी-चोटी लगाकर विरोध किया। 1947 से लेकर 1951 के मध्य उन्होंने राजगोपालाचारी 'राजाजी', के. एन. पनिक्कर, दिग्विजय सिंह 'जामसाहब', के. एम. मुंशी, आर. आर. दिवाकर सहित पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान तक को पत्र लिखे। नेहरू का स्पष्ट मत था कि सोमनाथ मंदिर के निर्माण में किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता, सरकारी पैसा और सरकार से संबंधित व्यक्ति शामिल नहीं होना चाहिए।

जेठालाल जोशी लिखते हैं, 'सरदार पटेल जूनागढ़ से सोमनाथ गए थे। वहां मंदिर की दुर्दशा देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। वहीं से वह सागर किनारे गए। हाथ में समुद्र का जल लेकर सोमनाथ मंदिर को पुनर्स्थापित करने का संकल्प लिया। यह बात पूरे देश में जंगल की आग की तरह फैल गई।' वहां से आने के बाद सरदार पटेल ने के. एम. मुंशी को लिखे पत्र में सोमनाथ को हिंदू भावना और अस्मिता के लिए अत्यंत आवश्यक माना, जिसे मुंशी ने 'पिलग्रीमेज टू फ्रीडम' पुस्तक में उद्धृत किया। वह कहते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में केवल जीर्णोद्धार से हिंदू भावना तृप्त नहीं होगी, उसके लिए प्रतिमा की पुनर्स्थापना भी हिंदू जनता के लिए आवश्यक है।

सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण और उद्घाटन में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का जवाहरलाल नेहरू ने एड़ी-चोटी लगाकर विरोध किया। 1947 से लेकर 1951 के मध्य उन्होंने राजगोपालाचारी 'राजाजी', के. एन. पनिक्कर, दिग्विजय सिंह 'जामसाहब', के. एम. मुंशी, आर. आर. दिवाकर सहित पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान तक को पत्र लिखे। नेहरू का स्पष्ट मत था कि सोमनाथ मंदिर के निर्माण में किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता, सरकारी पैसा और सरकार से संबंधित व्यक्ति शामिल नहीं होना चाहिए। लेकिन मंदिर निर्माण पूरी तरह से हिंदू समाज और प्रमुख हिन्दू राजाओं और व्यापारियों के आर्थिक सहयोग से पूर्ण हुआ था। सरदार पटेल और वी. एन. गाडगिल ने पचास लाख रुपए का चंदा एकत्र कराया। सोमनाथ के पुनर्निर्माण का विषय कैबिनेट मीटिंग में सरदार पटेल ने उठाया था, इसका विरोध करते हुए मौलाना आजाद ने कहा था कि मंदिर जैसा है, उसे वैसा ही रहने दिया जाए। जब गाडगिल ने इसे केंद्रीय सार्वजनिक कार्य विभाग के माध्यम से कराने का प्रस्ताव दिया तो नेहरू ने उसका विरोध किया।

जेठालाल जोशी के अनुसार, गाडगिल जो पीडब्ल्यूडी मंत्री भी थे, वह लिखते हैं कि मंदिर पुनर्निर्माण में सरकार का सिर्फ एक लाख रुपया खर्च हुआ था। मैने कहा जहां हम मस्जिदों और मकबरों को अनेकों अनुदान और छूट दे रहे हैं, तो हिन्दू मंदिर के जीर्णोद्धार में पैसा देना कैसे अनुचित है? बल्कि इससे सरकार को बहुसंख्य हिंदुओं की सद्भावना मिलेगी। इसने सौराष्ट्र का एकीकरण आसान बना दिया था। इसके लिए जामसाहब की अध्यक्षता में एक ट्रस्ट बनाया गया, जिसने सारे काम की देखरेख की। जामसाहब सौराष्ट्र रियासत से राजप्रमुख भी थे। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद मंदिर की पुनर्प्रतिष्ठा के लिए राष्ट्रपति डा. राजेंद्र प्रसाद को आमंत्रित किया गया, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। किंतु नेहरू ने जामसाहब और राजेंद्र प्रसाद के शामिल होने पर कड़ी आपत्ति जताई थी। 11 मार्च 1951 को राजाजी को लिखे पत्र में मंदिर के पुनर्निर्माण के पश्चात हो रहे उद्घाटन समारोह से राजेंद्र प्रसाद को अलग रहने की सलाह का उल्लेख किया गया है। उनके

मंदिर जाने की योजना के विरोध में 10 मार्च 1951 को नेहरू ने पत्र लिखा था, यह राष्ट्रपति सचिवालय में फाइल संख्या 59/51 में दर्ज है। 17 अप्रैल 1951 को नेहरू ने के. एम. पनिक्कर को लिखे पत्र मे भी इस बात का उल्लेख किया है कि वह राजेंद्र प्रसाद के सोमनाथ मंदिर उद्घाटन में जाने से दुखी हैं और उन्हें रोक पाने में असहाय अनुभव करते हैं।

मंदिर निर्माण सिर्फ राष्ट्रीय ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय चर्चा का भी विषय बन गया था। एक तरफ सरदार पटेल, के. एम. मुंशी, वी. एन. गाडगिल मंदिर में ज्योतिर्लिंग के रूप में विश्वात्मा की पुनर्स्थापना कर रहे थे, तो दूसरी ओर पाकिस्तान और अन्य मुस्लिम देशों में इसके विरुद्ध भ्रामक प्रचार किया जा रहा था। पाकिस्तानी समाचारपत्रों में यह समाचार प्रकाशित किए जा रहे थे कि सोमनाथ मंदिर को पुनः ध्वस्त करने के लिए वह दूसरा महमूद गजनवी पैदा करेंगे। मंदिर के लिए अनेकों भारतीय दूतावासों से विश्व की प्रमुख नदियों, पर्वतों और शहरों से जल, पत्थर और मिट्टी एकत्र करने का अभियान चलाया गया, जिसका भी नेहरू ने तीखा विरोध किया।

17 अप्रैल 1951 को के. एम. मुंशी को लिखे पत्र में पीकिंग (वर्तमान बीजिंग) में भारतीय दूतावास से ह्वांग हो, याग्त्से और पर्ल नदी का जल तथा शियान पर्वत का पत्थर का टुकड़ा भेजने की व्यवस्था करने का उल्लेख है, जिसे नेहरू ने सक्रिय होकर रोक दिया था। उन्होंने लिखा कि मंदिर के इस कार्य में दूतावासों को शामिल करने की बात जानकर उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। 9 मई 1951 को विदेश सचिव एस. दत्त को लिखे नोट में उन्होंने इसे सर्वाधिक दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया। अफगानिस्तान से मंदिर का दरवाजा वापस मंगाने की अफवाह पाकिस्तान के समाचारपत्रों में प्रकाशित हुई। इस पर भी नेहरू ने लियाकत अली को 21 अप्रैल 1951 को पत्र लिखकर सफाई दी थी। 22 अप्रैल 1951 को जामसाहब को पत्र लिखकर कहा कि पाकिस्तान इस कार्यक्रम का लाभ उठा कर यह सिद्ध करना चाहता है कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है। वास्तव में विचार किया जाए तो नेहरू को भारत के हिंदू बहुसंख्य जनता की भावनाओं से ज्यादा, पाकिस्तान क्या सोचता है? इसकी चिंता थी। नेहरू ने मंदिर उद्घाटन समारोह का रेडियो प्रसारण बाधित करने का प्रयास भी किया। 28 अप्रैल 1951 को आर. आर. दिवाकर को पत्र लिखकर उन्होंने मंदिर समारोह का प्रसारण कमजोर करने का निर्देश स्पष्ट रूप में दिया था।

अमृत महोत्सव का अर्थ

सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने पर भव्य उत्सव और जलाभिषेक के आयोजन से छात्रों और युवाओं में अपने इतिहासबोध की पुनर्दृष्टि प्राप्त होती है। मुस्लिम आक्रमण हों या यूरोपियन उपनिवेशवाद, इनके साम्राज्य की नींव और भवन, हमेशा हिंदू मंदिरों और आस्थाओं को तोड़कर ही बने। सोमनाथ जीर्णोद्धार का अमृत महोत्सव इतिहास, धर्म और आस्था की प्रबलता का बोध कराता है। साथ ही उन संकटों के प्रति सचेत भी करता है, जो स्वार्थी राजनीति और हिंदू विरोधी धर्मांधता के रूप में सक्रिय रहती है। ■

(लेखक दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंतरराष्ट्रीय अध्ययन संस्थान में एसोसिएट प्रोफेसर है।)

बंग-विजय का निहितार्थ

■ बी. संजय

चार मई 2026 का दिन पश्चिम बंगाल ही नहीं, भारतवर्ष के इतिहास में एक लंबे समय तक याद किया जाएगा। ऐसा मात्र इसलिए नहीं कि इस दिन राज्य की जनता ने राजनीतिक परिवर्तन कर दिया, बल्कि पंद्रह वर्षों से चली आ रही अल्पसंख्यक तुष्टिकरण की आधारशिला पर केंद्रित सत्ता बनाए रखने के लिए बहुसंख्यक हिन्दू समाज को अस्तित्व विहीन करने का प्रयास करने वाली ममता सरकार को उलट कर रख दिया।

ऐसा इसलिए भी नहीं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने वैचारिक जगत में इस विजय के वैश्विक महत्व एवं भारत सरकार के बढ़ते कद को देखते हुए स्वयं उन्हें बधाई दी और ह्वाईट हाउस ने इस सम्बन्ध में प्रेसनोट जारी किया। वैश्विक स्तर पर पत्र-पत्रिकाओं के धुरंधर समालोचक विवशतापूर्ण समालोचनाएं लिखते हुए भी इस अध्याय को रेखांकित करने के लिए विवश दिखाई दिए। वस्तुतः यह दिन इसलिए इतिहास के स्मृति पटल पर छाया रहेगा क्योंकि भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के उस औरस-अविरल प्रवाह, जिसकी कसौटी पर खड़े होकर इस राष्ट्र और इसकी तमाम पीढ़ियों ने पुनः पुनः अपनी सभ्यता एवं संस्कृति की ध्येय दृष्टि एवं प्रवाह मार्ग को परिभाषित करते हुए अपने अस्तित्व को अक्षुण्ण बनाए रखा है, जो बंगाल (अविभक्त या उसके बाद) किंचित कारणों से दिग्भ्रमित हो गया था, उस बंग-हृदय ने अपनी लंबी घोर निद्रा से किंचित मुक्ति प्राप्त कर ली।

1905 में लार्ड कर्जन द्वारा बंग-भंग की निर्णय के विरोध के पृष्ठभूमि में मौजूद सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के उस औरस-अविरल धारा ने 1905 से 2026 तक के 121 वर्षों बाद पुनः स्वयं का साक्षात्कार किया है। बंगाल विभाजन का निहितार्थ निर्विवाद रूप से भारत की उस

राष्ट्रवादी मानसिकता को विखंडित करके प्रभावहीन करना था, जिसे वंदे मातरम् जय घोष के रचयिता एवं राष्ट्रकवि बंकिम चन्द्र चटर्जी हों, कलकत्ता उच्च न्यायालय के तत्कालीन न्यायाधीश, बैरिस्टर और बंगाल टाईगर कह जाने वाले सर आशुतोष मुखर्जी हों जो बाद में कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति बने, प्रेसीडेंसी कॉलेज में उनके सहपाठी एवं अनन्य मित्र नरेंद्र नाथ दत्त हों, जिन्हें विश्व पटल पर भारत का नाम रोशन करने वाले राष्ट्रनायक स्वामी विवेकानंद के नाम से जाना गया, ऋषि अरबिंदो हों या डा. हेडगेवार, सभी ने एक रुप में ही अनुभूत किया था।

धरातल विहीन वामपंथियों की यूटोपियन सोच से पश्चिम बंगाल का युवा बौद्धिक दिवालियापन का शिकार हो रहा था। अभाविप ने इस बौद्धिक षड़यंत्र को न केवल समझा, बल्कि इस चुनौती को स्वीकार कर विमर्श के सभी स्तरों पर इसका सामना किया। राष्ट्रनायक स्वामी विवेकानन्द अभाविप कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत हैं। अभाविप के अनवरत हस्तक्षेप ने बंगाल के छात्रों, युवाओं को सम्भवतः स्वामी विवेकानंद से पुनः परिचय कराया।

कविगुरु रवींद्रनाथ टैगोर ने गंगा तट पर लोगों को राखी बांधी और कलकत्ता के टाऊन हॉल में विशाल सभाएं आयोजित कर विभाजन का विरोध किया था। अलीपुर जेल से बाहर आने के बाद उत्तरपाड़ा में दिए भाषण में अरबिन्दो घोष ने घोषित किया कि पहले मैं यह सोचता था कि राष्ट्र के लिए कार्य करना ही धर्म है, पर अपनी गहन साधना के उपरांत मैंने अनुभूत किया कि राष्ट्रीयता एक विश्वास है, एक धर्म है, एक निष्ठा है, बल्कि मैं कहता हूं कि सनातन धर्म ही हमारे लिए राष्ट्रीयता है। बंग-भंग के उपरांत ही वंदे मातरम् का जयघोष ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया।

1908 में बालक केशव ने उसी वंदे मातरम् का अपनी कक्षा में उद्घोष कर विद्यालय निष्कासन को स्वीकार किया। बाद में उन्होंने यवतमाल से पढ़ाई पूरी की। मैट्रिक का प्रमाणपत्र उन्हें प्रख्यात क्रांतिकारी डा. रास बिहारी घोष द्वारा प्रदान किया गया, जिसने उनके कलकत्ता आने, मेडिकल की पढ़ाई और अनुशीलन समिति से जुड़ने का मार्ग प्रशस्त किया। सुरेन्द्र नाथ बनर्जी सहित लाल-पाल-बाल सभी इसी राष्ट्रवादी सोच से ओतप्रोत थे।

संघ प्रतिष्ठाता डा. केशव बलिराम राव हेडगेवार ने कलकत्ता मेडिकल कालेज से मेडिकल की शिक्षा पूरी की थी। 1910 से 1916 तक वह कलकत्ता में ही रहे। जून 1916 में उनकी लाइसेंसिएट इन मेडिसिन एण्ड सर्जरी की शिक्षा पूरी हुई। शिक्षा के दौरान वह प्रख्यात क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति के सक्रिय सदस्य रहे।

औपचारिक रूप से 22 मार्च 1939 को मुर्शिदाबाद के सारगाछी आश्रम में स्वामी अखंडानंद (स्वामी रामकृष्ण परमहंस के तीन प्रमुख शिष्यों में से एक) के शिष्य माधव सदाशिव राव गोलवलकर, जो बाद में संघ के द्वितीय सरसंघचालक बने, की पहल पर कलकत्ता के माणिकतला में संघ की पहली शाखा आरंभ हुई। विगत 87 वर्षों का संघ कार्य या यूं कहें कि 116 वर्षों (1910-2026) की तपस्या अब आकर साकार हुई है। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन का दिन और क्षण संघ के अलग-अलग पीढ़ियों के तमाम स्वयंसेवकों एवं संघ परिवार के विविध क्षेत्रों में कार्य कर रहे कार्यकर्ताओं विशेष रूप से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) के हजारों कार्यकर्ताओं के लिए एक भाव-विह्वल कर देने वाला क्षण था।

अभाविप, जिसकी स्थापना संघ के बीज मंत्र 'परं वैभवं नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम' को साकार करने के लिए मनसा-वाचा-कर्मणा समर्पित मनीषियों के भाव एवं विश्व में राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के व्यापक परिप्रेक्ष्य में छात्रों-युवाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के दृढ़ संकल्प के साथ हुई थी। अभाविप ने छात्र-प्राध्यापक के समुच्चय के साथ इस दायित्व के समुचित निर्वहन के लिए छात्र संगठन, उसका वैचारिक दर्शन, अभिनव कार्य प्रणाली की रचना की और राष्ट्रव्यापी संरचना के संयोजन से सभी आपतित प्रश्नों पर राष्ट्रवादी दृष्टिकोण को मुखरित करते हुए उसके समाधान के लिए सर्वोच्च बलिदान तक संघर्ष की परम्परा विकसित की। अभाविप

परिवार के लिए यह वह स्वर्णिम क्षण था, जब वह बंगाल में राष्ट्रीय सीमाओं को सुरक्षित रखने, राष्ट्रवादी सोच को युवाओं में बनाए रखने, बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकने, विधर्मियों एवं राजनीतिक गठजोड़ के कारण विशेष रूप से महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए किए गए अनवरत संघर्ष एवं बलिदानों को सार्थक होता देख रहा था।

शनैः शनैः हो रहे क्रांतिकारी परिवर्तन का परिणाम अवश्यंभावी होता है। पश्चिम बंगाल में जो हुआ, वह उसी अनवरत जारी परिवर्तन का परिणाम है। अभाविप के नेतृत्व में छात्र-सक्रियता की लम्बी यात्रा में अनेकों उल्लेखनीय ऐसे पड़ाव भी आए, जब अभाविप को पश्चिम बंगाल के सार्वजनिक मंच पर व्यापक आंदोलनों को संचालन करना पड़ा।

सीमान्त सुरक्षा के लिए तीन बीघा आंदोलन, बांग्लादेशी घुसपैठ और मुस्लिम तुष्टिकरण के विरुद्ध अभियान, कश्मीर बचाओ आंदोलन, कलकत्ता स्थित आर. जी. कर. मेडिकल कालेज में प्रशिक्षु महिला डाक्टर की बलात्कार के बाद निर्मम हत्या के विरुद्ध अभाविप का देशव्यापी आंदोलन, संदेशखाली में तत्कालीन सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के नेताओं द्वारा महिला उत्पीडन के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी आंदोलन, ममता बनर्जी की निर्दयता के कारण छात्रों को मिली मौत के विरुद्ध हुए आंदोलन ऐसे निर्णायक मोड़ थे, जहां अभाविप कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल के जनमानस को झकझोरा और विचार करने के लिए बाध्य किया। इसके साथ ही सबसे प्रमुख चुनौती और जिसके विरुद्ध अभविप को निर्णायक लड़ाई लड़नी पड़ी, वह थी पश्चिम बंगाल के जनमानस, युवाओं और बौद्धिक जगत को दिग्भ्रमित सोच से मुक्ति दिलाकर राष्ट्रवादी सोच की मुख्य धारा से जोड़ना और अभाविप ने इस दायित्व का निर्वहन किया।

बंगाल टाईगर के पुत्र, हिन्दू महासभा के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने बहुसंख्यक हिन्दू समाज की रक्षा के लिए कलकत्ता को बंग्लादेश में जाने से रोका और धारा-370 के तहत कश्मीर को भारत से अलग करने की कोशिश को रोकने के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी, वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल के युवाओं और बौद्धिक जगत की नजरों में साम्प्रदायिक घोषित किए जा चुके थे। जिन स्वामी विवेकानंद ने हिन्दू सन्यासी होने के अतिरिक्त अपना कोई परिचय नहीं दिया, वामपंथी प्रभाव में आकर उनके द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन ने स्वयं के लिए 'रामकृष्णइज्म' के नाम पर हिन्दू धर्म से अलग पहचान के लिए उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल की और राष्ट्रवादी विचारों के पुरोधा स्वामी विवेकानंद को तब तक एक अलग रंग में रंगने की कोशिश करता रहा, जब तक उच्चतम न्यायालय नकारा। 'शिवाजी उत्सव' शीर्षक कविता के रचयिता कविगुरु रवींद्रनाथ जो 'एक धर्मराज्य के रूप में खंडित भारत को वीर राजा छत्रपति शिवाजी के द्वारा एक सूत्र में पिरोने के' स्वप्नद्रष्टा हैं, उन्हें भी राष्ट्रवादी विचारों के प्रति एक 'जड़ चिन्तक' के रूप में प्रस्तुत किया गया।

धरातल विहीन वामपंथियों की यूटोपियन सोच से पश्चिम बंगाल का युवा बौद्धिक दिवालियापन का शिकार हो रहा था। अभाविप ने इस बौद्धिक षड़यंत्र को न केवल समझा, बल्कि इस चुनौती को स्वीकार कर विमर्श के सभी स्तरों पर इसका सामना किया। राष्ट्रनायक स्वामी विवेकानन्द अभाविप कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत हैं। अभाविप के अनवरत हस्तक्षेप ने बंगाल के छात्रों, युवाओं को सम्भवतः स्वामी विवेकानंद से पुनः परिचय कराया।

'उतिष्ठित जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत (उठो, जागो और तब तक नहीं रूको, जब तक तुम अपने लक्ष्य को न प्राप्त कर लो)' उनके द्वारा दोहराया जाना वाला कठोपनिषद् का यह मंत्र अभाविप कार्यकर्ताओं का ध्येय वाक्य बन गया। स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 को शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में अपना ऐतिहासिक भाषण दिया था। उसी 11 सितंबर को 1990 में अभाविप ने 'कश्मीर बचाओ आंदोलन' किया, जब देश भर से आए दस हजार से अधिक छात्र-छात्राओं ने कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराया। यह वह अवसर था, जिसने सम्पूर्ण भारत के साथ ही पश्चिम बंगाल की सुषुप्त मनीषा के अंतःस्थल को भी झकझोर दिया। अभाविप ने अहसास कराया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी साम्प्रदायिक नहीं, बल्कि राष्ट्र की अखण्डता की बलि वेदी पर प्राण न्यौछावर करने वाले राष्ट्र-नायक थे।

पांडिचेरी आश्रम में अखण्ड भारत के मानचित्र के समक्ष साधनारत ऋषि अरबिंदो और बंग-भंग को रोकने के लिए आबालवृद्ध को राखी बांधते कविगुरु रवींद्रनाथ टैगोर की छवि को पुनः प्रतिष्ठित करने का श्रेय संघ

परिवार और अभाविप कार्यकर्ताओं को दिया जाता है। अभाविप कार्यकर्ता शांतनु सिंह की पुस्तक 'ओरा शुधू भूल कोरे जाए (वे केवल भूल करते जाते हैं)', अभाविप के तत्कालीन क्षेत्रीय संगठन मंत्री वी. सतीश एवं पश्चिम बंगाल के प्रदेश संगठन मंत्री स्वर्गीय तपन घोष के संरक्षण में प्रकाशित पत्रिका बंग-विद्यार्थी और स्वस्तिका के लेखों ने अलख जगाई।

पूर्व राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री हरेन्द्र प्रताप, पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री स्वर्गीय सुशील मोदी, अभाविप-पश्चिम बंगाल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डा. कल्याण व्रत भट्टाचार्य के विश्लेषणों एवं संघ के तत्कालीन क्षेत्रीय प्रचारक सत्य व्रत मजूमदार के अकाट्य तर्कों एवं भाषणों ने वामपंथ की कलई खोल कर रख दी। राष्ट्रवादी चिंतक दत्तोपंत ठेंगड़ी की 'द थर्ड वे, मार्क्स एण्ड दीनदयाल : टू डिफरेंट एप्रोचेज' एवं एच. वी. शेषाद्रि की पुस्तक आरएसएस विजन इन एक्शन, द ट्रेजिक स्टोरी आफ पार्टिशन आदि पुस्तकों ने वैचारिक क्रांति लाने ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया।

पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के समय वामपंथी साहित्य की बिक्री के लिए स्टाल लगाए जाते थे, लेकिन अभाविप ने उन्हीं स्थानों से राष्ट्रवादी साहित्य को बौद्धिक जगत में लोकप्रिय बनाया। यह वामपंथी तंत्र के विरुद्ध संघ परिवार के कार्यकर्ताओं का आमने-सामने से होने वाले संघर्ष जैसा था। संघ स्वयंसेवकों एवं परिवार के कार्यकर्ताओं ने हर कीमत चुकाने के बाद भी मैदान नहीं छोड़ा। वर्तमान पीढ़ी की सोच, समर्पण एवं सक्रियता ने उसी मैदान को जीत के मैदान में बदल दिया।

4 मई 2026 को पश्चिम बंगाल में राष्ट्रवादी विचारधारा को मिली विजय इसी विचार और अनवरत साधना के मार्ग का एक सुखद पड़ाव कहा जा सकता है, लेकिन पथिक तुम्हें तो दूर जाना है। जैसा कि अभाविप के शिल्पकार श्रद्धेय यशवंत राव केलकर का उल्लेख करते हुए अभाविप के पूर्व राष्ट्रीय संगठन मंत्री एवं वर्तमान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले कहते हैं कि अभाविप का कार्य राष्ट्र कार्य के विविध क्षेत्रों के लिए उपयुक्त कार्यकर्ता प्रदान करना है और लक्ष्य परमवैभवमय भारत है। इसलिए निरलस चलते रहो, चरैवेति-चरैवेति। ■

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।)

। प्रतिक्रिया ।

विकासोन्मुखी जनभावनाओं का परिचायक हैं चुनाव परिणाम: अभाविप

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल एवं पुडुचेरी के विधानसभा चुनावों में आए जनादेश का स्वागत करते हुए कहा है कि इन चुनावों के परिणाम देश की लोकतांत्रिक चेतना की परिपक्वता का सशक्त प्रमाण हैं। व्यापक जनभागीदारी एवं युवाओं की सक्रिय उपस्थिति यह दर्शाती है कि देश का मतदाता अधिक सजग, जिम्मेदार और राष्ट्रहित के प्रति प्रतिबद्ध हो चुका है। विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में प्राप्त जनादेश एक ऐतिहासिक परिवर्तन का संकेत देता है। यह परिणाम केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि भयमुक्त, विकासोन्मुख और राष्ट्रवादी शासन व्यवस्था की स्थापना का स्पष्ट संदेश है।

चुनाव परिणाम आने के बाद अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री डा. वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में वर्षों से अभाविप ने शिक्षा, नारी सुरक्षा, छात्र अधिकार, रोजगार एवं अवैध घुसपैठ जैसे मुद्दों को लेकर निरंतर संघर्ष किया। यह जनादेश उन सभी प्रयासों को नई ऊर्जा प्रदान करता है और यह विश्वास जगाता है कि प्रदेश अब एक भयमुक्त और सुशासित वातावरण की ओर अग्रसर होगा। लंबे समय से प्रदेश में व्याप्त राजनीतिक हिंसा, अराजकता, सिंडिकेट संस्कृति, शिक्षा में गिरावट, महिला असुरक्षा, बांग्लादेशी घुसपैठ तथा रोजगार के सीमित अवसरों के विरुद्ध जो जनभावना विकसित हो रही थी, वह स्पष्ट रूप से परिणामों में परिलक्षित हुई है। अभाविप इस जनादेश का स्वागत करते हुए उम्मीद करती है कि नई शासन व्यवस्था प्रदेश को हिंसा और भय से मुक्त कर विकास, पारदर्शिता और राष्ट्रीय मूल्यों पर आधारित एक सशक्त दिशा प्रदान करेगी। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

Bharat's Vision for Responsible Artificial Intelligence

In a significant step towards shaping India's artificial intelligence ecosystem with a 'Nation First' approach, the AdhyAI Summit 2026-A New Chapter of Bharat's AI was organised at the D&V Lecture Hall Complex of Indian Institutes of Technology (IIT-BHU) Varanasi. The summit, jointly organised by Think India in collaboration with IIT (BHU), brought together academicians, policymakers, researchers, innovators and students to deliberate on the future of responsible AI in India.

The one-day summit, held on April 8, witnessed the participation of over 400 delegates, including 42 hackathon teams and more than 86 young innovators from institutions across the country. Discussions throughout the event focused on ethical AI adoption, digital inclusion, AI-driven innovation and India's growing technological leadership in the global arena.

The inaugural session set the tone for the summit with thought-provoking addresses by eminent personalities. Prof. Manindra Agrawal described AI as a transformative force capable of redefining problem-solving across sectors. He emphasised the need for students to understand the mechanics of AI rather than becoming passive users of technology. Highlighting the importance of original thinking, he proposed the idea of a 'Cognitive Gym' where individuals could train their minds to remain creative and independent in the AI age.

Prof. Ajit Kumar Chaturvedi urged students to adopt AI with responsibility and awareness. Stressing the idea of 'Conscious AI' or 'Sajag AI', he warned against becoming 'mindless consumers' of technology and encouraged youth to align innovation with social responsibility and national development.

Prof. Amit Patra underlined the importance of domain knowledge alongside technical expertise. Drawing parallels with the arrival of computers decades ago, he stated that AI should be seen not merely as a tool but as a national vision capable of solving local challenges and strengthening India's technological standing globally.

Joining virtually, Sunil Kumar Sharma appreciated the initiative and emphasised the role of technology in bridging the digital divide, solving rural problems and contributing towards the vision of a 'Viksit Bharat'.

A major attraction of the summit was the AI Hackathon, where teams presented innovative solutions addressing real-world challenges in infrastructure, governance, healthcare and

agriculture. Participants utilized advanced AI frameworks and large language models to build socially relevant applications. The projects were evaluated on technical feasibility, innovation and societal impact by a distinguished jury comprising academic and industry experts.

The summit also featured a high-level panel discussion on 'AI in Various Fields', moderated by experts from technology, healthcare, agriculture and legal sectors. Discussions revolved around the application of AI in farming, medical diagnostics, judiciary systems and governance. Experts highlighted both the opportunities and ethical challenges associated with AI deployment in India.

Agriculture expert Dr. V. K. Tripathi spoke about AI-powered farming solutions, including robotic harvesting and disease detection systems, while Dr. Saurabh Singh emphasized that AI in healthcare should complement, not replace, human empathy. Legal expert Adv. Varun Singh cautioned against overdependence on AI in judicial systems, pointing out concerns related to false citations and ethical accountability.

The valedictory ceremony concluded with the felicitation of hackathon winners and a collective call for continued innovation in the service of the nation. Organisers encouraged students to convert their ideas into scalable solutions capable of addressing India's unique challenges. ■

(Rashtriya Chhatrashakti Team)

I दिल्ली I

शैक्षणिक एवं बुनियादी ढांचे से जुड़े सुधारों की मांग

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप)-दिल्ली ने छात्रों की मूलभूत समस्याओं और अधिकारों को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में 'छात्र अधिकार मार्च' का आयोजन किया। मार्च में विश्वविद्यालय के विभिन्न कालेजों से आए हजारों छात्र-छात्राओं ने हिस्सा लिया। अभाविप ने प्रशासन के समक्ष छात्रों के शैक्षणिक और बुनियादी ढांचे से जुड़े सुधारों पर केंद्रित बारह प्रमुख मांगों संबंधी एक मांगपत्र भी सौंपा।

गत 21 अप्रैल को निकाले गए मार्च के बाद अभाविप ने विश्वविद्यालय प्रशासन से की गई मांगों में विश्वविद्यालय को 'पोर्टा केबिन' मुक्त बनाना, अनिवार्य फायर सेफ्टी ऑडिट सुनिश्चित करने और गत 30 अप्रैल तक परीक्षा फॉर्म के विलंब शुल्क से छूट दिलाना शामिल है। इसके अतिरिक्त अभाविप ने पांच वर्षीय विधि पाठ्यक्रम के शुल्क को घटाने, अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए पूरक परीक्षा का आयोजन, नए हॉस्टलों का निर्माण और एक 'सेंट्रलाइज्ड प्लेसमेंट सेल' की स्थापना की मांग भी की है। सामाजिक समावेशिता को बढ़ावा देते हुए अभाविप ने थर्ड जेंडर छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा और विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे को दिव्यांग सुगम्य बनाने पर भी विशेष जोर दिया है। अभाविप ने 'एक कोर्स-एक फीस' और अकादमिक काउंसिल में छात्रों के प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए कालेज कैंटीन में स्वच्छता और भोजन की गुणवत्ता बनाए रखने की भी अपील की है।

अभाविप दिल्ली प्रांत मंत्री सार्थक शर्मा के अनुसार 'छात्र अधिकार मार्च' दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन की उदासीनता के विरुद्ध छात्रों का एक निर्णायक शंखनाद है। अभाविप ने जिन मांगों को उठाया है, वह छात्रों के भविष्य और उनकी सुरक्षा से जुड़ी हुई हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन यदि मांगों पर सकारात्मक कदम नहीं उठाता है, तो अभाविप छात्र हितों की रक्षा के लिए और भी उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

सिएटल में लगी स्वामी विवेकानंद की पहली प्रतिमा

सिएटल नगर अमेरिका का ऐसा पहला नगर बन गया है, जिसने वेस्टलेक स्क्वायर पार्क में स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा स्थापित की है। इस आदमकद कांस्य प्रतिमा का अनावरण स्थानीय मेयर सुश्री केटी विल्सन और सिएटल में भारत के महावाणिज्य दूत प्रकाश गुप्त ने संयुक्त रूप को गत 11 अप्रैल को किया। स्वामी विवेकानंद की यह पहली ऐसी प्रतिमा है, जिसे अमेरिका में किसी नगर निकाय द्वारा स्थापित किया गया है। यह प्रतिमा प्रसिद्ध भारतीय कलाकार नरेश कुमार कुमावत द्वारा बनाई गई है और उस आध्यात्मिक गुरु को एक श्रद्धांजलि है, जिन्होंने 1883 में पश्चिमी विश्व को भारतीय दर्शन और वेदांत से परिचित कराया था। अधिकारियों के अनुसार भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) दिवस के अवसर पर प्रतिमा का अनावरण किया गया और यह भारत की व्यापक सांस्कृतिक कूटनीति पहलों का हिस्सा है। सिएटल को भारतीय-अमेरिकी समाज और भारत एवं अमेरिका के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान के केंद्र के रूप में इसकी बढ़ती भूमिका के कारण चुना गया। यह प्रतिमा केवल एक धार्मिक स्मारक नहीं है, बल्कि विश्व बंधुत्व, शांति और वैश्विक युवाओं के लिए उनके संदेश की कालातीत प्रासंगिकता का प्रतीक है। प्रतिमा की स्थापना स्वामी विवेकानंद के बौद्धिक और आध्यात्मिक योगदान की वैश्विक मान्यता में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखी जा सकती है। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

वंदे मातरम के अपमान पर सजा का प्रावधान

भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान जन-गण-मन के समान वैधानिक दर्जा देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम-1971 में संशोधन किए जाने संबंधी ऐतिहासिक प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दे दी है। प्रस्ताव के अनुसार राष्ट्रीय गीत का अपमान एक संज्ञेय अपराध होगा। इस निर्णय का उद्देश्य राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की ऐतिहासिक भूमिका को औपचारिक मान्यता देना है।

राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम-1971 के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान का अपमान एक दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है, जिसके लिए कारावास या जुर्माना या दोनों सजा दिए जाने का प्रावधान है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति के बाद राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम में संशोधन के लिए प्रस्तावित संशोधन प्रस्ताव को संसद में पारित कराया जाएगा। संसद से प्रस्तावित संशोधन प्रस्ताव पारित होने के बाद राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के गायन के समय व्यवधान उत्पन्न करना, अपमान करना या अवरोध पैदा करना दंडनीय अपराध होगा और ऐसे मामलों में भी अभी राष्ट्रगान के अपमान से जुड़े मामलों में लागू होने वाले सभी कानूनी प्रावधान लागू होंगे।

राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर गत फरवरी माह में केंद्र सरकार ने आधिकारिक कार्यक्रमों में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम संबंधी एक औपचारिक संहिता जारी की थी। संहिता में सरकारी एवं आधिकारिक कार्यक्रमों में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के सभी छह श्लोक के गायन या वादन के साथ ही गीत के सम्मान में उपस्थित लोगों को सावधान मुद्रा में खड़ा होना अनिवार्य किया गया है। साथ ही यदि किसी कार्यक्रम में राष्ट्रीय गान जन-गण-मन और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम दोनों को गायन या वादन होता है, तो सबसे पहले राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को प्रस्तुत करना होगा। इन नियमों का उद्देश्य राष्ट्रगीत के सम्मान के साथ ही देशभक्ति की भावना को मजबूत करना है। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

एनटीए मुख्यालय पर अभाविप का धरना-प्रदर्शन

परीक्षा प्रणाली में व्यापक संरचनात्मक सुधार की मांग

राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) का पेपर लीक होने का मामला सामने आने के बाद परीक्षा प्रक्रिया में लगातार उजागर हो रही अनियमितताओं तथा विद्यार्थियों के भविष्य के साथ हो रहे गंभीर खिलवाड़ के विरुद्ध अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने राजधानी दिल्ली स्थित नेशनल टेस्टिंग एजेंसी

(एनटीए) मुख्यालय के बाहर धरना-प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से परीक्षा प्रणाली में व्यापक संरचनात्मक सुधार करते हुए निजी एजेंसियों पर निर्भरता समाप्त करने की मांग की। गत 13 मई को आयोजित प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए अभाविप के कई कार्यकर्ताओं एवं विद्यार्थियों को हिरासत में भी लिया।

एनटीए मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे अभाविप कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री डा. वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं के संचालन में एनटीए कई बार विफल रही है। नीट-यूजी पेपर लीक होने का यह पहला मामला नहीं है। गत कई वर्षों से अनेकों परीक्षाओं के पेपर लीक होने से छात्रों को हानि उठानी पड़ी है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि परीक्षा संचालन कार्य के लिए एनटीए पूरी तरह सक्षम नहीं है और इसके पीछे एक संगठित गिरोह सक्रिय है। इससे पहले भी अभाविप परीक्षाओं को पूर्णतः पारदर्शी और सुरक्षित बनाने की मांग करती रही है।

अभाविप का स्पष्ट मत है कि राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में बार-बार सामने आने वाली गड़बड़ियां देश के लाखों विद्यार्थियों के परिश्रम, विश्वास और भविष्य पर सीधा आघात हैं। नीट-यूजी जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा में पेपर लीक की घटना केवल एक प्रशासनिक विफलता नहीं, अपितु संपूर्ण परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्नचिह्न है। अभाविप मांग करती है कि नीट-यूजी पेपर लीक मामले की जांच निष्पक्ष, पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से कराई जाए तथा जांच से जुड़े तथ्यों को सार्वजनिक किया जाए, ताकि इस पूरे तंत्र को ध्वस्त किया जा सके, तभी देशभर के विद्यार्थियों का विश्वास पुनः स्थापित हो सकेगा। राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं का संचालन अस्थायी एवं आउटसोर्स आधारित व्यवस्था के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। प्रिंटिंग, परीक्षा केंद्र प्रबंधन तथा व्यवसाय प्रबंधन जैसी संवेदनशील जिम्मेदारियों को निजी एजेंसियों को सौंपना गंभीर सुरक्षा संकट को जन्म देता है, जिससे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति की आशंका बढ़ती है। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

पर्यावरण संरक्षण पर मंथन

विश्व पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में विकासार्थ विद्यार्थी द्वारा देश के विभिन्न प्रांतों में पर्यावरण संरक्षण से जुड़े अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान, संगोष्ठियां, जागरूकता रैली सहित अन्य गतिविधयां शामिल रहीं। उत्तर प्रदेश की राजधानी **लखनऊ** महानगर में गत 22 से 23 अप्रैल के मध्य लखनऊ विश्वविद्यालय में 'भूमि फेस्ट : आइडिया टू एक्शन' का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण नीति, युवा नेतृत्व, नवाचार और पर्यावरण उद्यमिता के लिए विद्यार्थियों, शिक्षाविदों एवं पर्यावरणविदों को एक साथ लाकर पर्यावरणीय जागरूकता को व्यवहारिक समाधानों में बदलने का सफल प्रयास करना रहा।

दो दिवसीय भूमि फेस्ट का शुभारंभ मुख्य अतिथि परमिंदर सिंह ने किया। फेस्ट में वैश्विक नीति पर 'कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज' एवं यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली विषयों पर चर्चा करते हुए प्रतिभागियों ने 2035 के लिए 'राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) लक्ष्यों' को मजबूत करने की रणनीतियों एवं 'जलवायु हानि एवं क्षति कोष' के लिए अनिवार्य वित्तीय योगदान स्थापित करने पर विचार-विमर्श किया गया। राष्ट्रीय स्मृति और पर्यावरणीय जिम्मेदारियों के उद्देश्य से फेस्ट में पहलगाम हमले में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ ही, 2016 वर्ग फीट में बायोडिग्रेडेबल कपों से भारत का बड़ा मानचित्र बनाया गया।

फेस्ट में हिस्सा लेने वाले विद्यार्थियों ने प्राकृतिक और ऊर्जा कुशल शीतलन प्रणाली, ऊर्जा कुशल स्मार्ट नगरों का फ्रेमवर्क, वायु एवं जल प्रदूषण की निगरानी एवं नियंत्रण के उपाय और पर्यावरण अनुकूल सतत विकास की अवधारणाओं पर आधारित प्रदर्शनी को प्रस्तुत किया। भूमि फेस्ट के दूसरे दिन पर्यावरण और नेतृत्व संबंधी पहलुओं पर दो विशेषज्ञ आधारित सत्र आयोजित किए गए, जिसमें इको उद्यमिता को व्यावहारिक करियर और लाभदायक ग्रीन बिजनेस मॉडल में बदलने के साथ ही विद्वानों ने युवाओं को भविष्य की पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए

संरचित मार्गदर्शन की आवश्यकता पर जोर दिया।

उधर प्रदेश के **बस्ती** नगर में गत 16 से 22 अप्रैल के मध्य 'कूआनो संरक्षण अभियान' चलाया गया। अभाविप की गतिविधि विकासार्थ विद्यार्थी-बस्ती तथा नगरपालिका-बस्ती के संयुक्त सहयोग से संचालित कूआनो नदी संरक्षण अभियान व्यापक, अनुशासित एवं प्रभावशाली रूप से संपन्न हुआ। यह अभियान केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति समाज की जागरूकता, युवाशक्ति के संकल्प और संस्थागत समन्वय का सशक्त प्रतीक बनकर उभरा।

कूआनो नदी को क्षेत्र की जीवनरेखा के रूप में जाना जाता है, लेकिन कई वर्षों से प्रदूषण, जलकुंभी के अत्यधिक प्रसार एवं ठोस कचरे के कारण नदी का स्वरूप प्रभावित हुआ है। नगरपालिका के सहयोग से चलाए गए अभियान में अभाविप कार्यकर्ताओं ने उल्लेखनीय समर्पण के साथ श्रमदान किया। कार्यकर्ताओं ने कूआनो नदी से बड़ी मात्रा में जलकुंभी, प्लास्टिक, पॉलिथीन, घरेलू अपशिष्ट एवं अन्य अवरोधों को हटाने का कार्य किया। कई स्थानों पर नदी का प्रवाह पूर्णतः अवरुद्ध हो चुका था, जिसे कार्यकर्ताओं के सतत प्रयासों से पुनः सुचारु किया गया। साथ ही नदी तट पर फैली गंदगी, झाड़ियां, सूखे अवशेष एवं स्थानीय स्तर पर मौजूद कचरे के ढेरों की सफाई कर क्षेत्र को स्वच्छ एवं व्यवस्थित बनाया गया। यह श्रमदान केवल सफाई तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने समाज में एक सकारात्मक चेतना भी विकसित की, जिससे स्थानीय नागरिकों की भागीदारी निरंतर बढ़ती गई।

विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर असम स्थित **काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान** में विकासार्थ विद्यार्थी द्वारा दो दिवसीय पर्यावरण नेतृत्व कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गत 22 से 26 अप्रैल तक आयोजित कार्यक्रम के पहले दिन उद्घाटन सत्र के साथ ही वन विभाग के अधिकारियों द्वारा वन्यजीवों की निगरानी के लिए ड्रोन का सार्वजनिक प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में 'अंडरस्टैंडिंग जियोडाइवर्सिटी : इनसाइट्स फ्रॉम काजीरंगा नेशनल पार्क' विषय पर प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए प्रो. हृषिकेश बरुआ ने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। प्रथम दिवस के दोनों सत्रों में पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता और पुनर्स्थापन से संबंधित महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जानकरियों से जुड़ा संवाद किया गया। कार्यक्रम के दूसरे दिन प्रतिभागियों ने विभिन्न प्रजाति के पक्षियों का अवलोकन करने के साथ ही करबी हिल्स और गांवों में स्थानीय लोगों से संपर्क करके स्थानीय संस्कृति एवं पारंपरिक भोजन का आनंद लिया।

कार्यक्रम के तीसरे दिन विकासार्थ विद्यार्थी के अखिल भारतीय प्रमुख राहुल गौड़ ने प्रतिभागियों के साथ पर्यावरणीय नेतृत्व की भूमिका और कर्तव्यों पर चर्चा की। पर्यावरणीय इतिहास और वर्तमान के कई उदाहरणों के माध्यम से उन्होंने प्रतिभागियों को पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया।

चौथे दिन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की निदेशक सोनाली घोष ने प्रतिभागियों के साथ वन्यजीव संरक्षण, पर्यावरणीय जिम्मेदारी तथा भारत के एक महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र के प्रबंधन से जुड़ी व्यावहारिक चुनौतियों के विषय में चर्चा की। बाद में प्रतिभागियों ने काजीरंगा राष्ट्रीय ऑर्किड पार्क का भ्रमण करके विभिन्न प्रकार की ऑर्किड प्रजातियों को देखा। बाद में इंडिया स्टार पैशन अवार्ड (2019) और गार्जियन ऑफ वाइल्ड लाइफ अवार्ड (2025) से सम्मानित मनोज गोगोई ने अपने संबोधन में पक्षियों, सर्पों और अन्य जीवों के संरक्षण और बचाव के महत्व पर विशेष जोर दिया। अंतिम दिवस पर विभिन्न गटों में विभाजित प्रतिभागियों ने अपनी-अपनी प्रस्तुतियों को सामने रखा। समापन सत्र में अभाविप पूर्वोत्तर क्षेत्र के क्षेत्रीय संगठन मंत्री कमल नयन एवं राष्ट्रीय मंत्री कमलेश सिंह उपस्थित रहे। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

विभिन्न मांगों को लेकर अभाविप का प्रदर्शन

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने दुमका स्थित सिदो कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर तालाबंदी कर धरना-प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर भ्रष्टाचार, अनियमितताओं एवं छात्र समस्याओं की अनदेखी का आरोप लगाया। छात्रों का कहना था कि छोटी-छोटी समस्याओं के समाधान के लिए उन्हें भटकना पड़ रहा है, जबकि विश्वविद्यालय प्रशासन मौन बना हुआ है।

अभाविप दुमका जिला संयोजक अभिषेक गुप्ता ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय एवं इसके अंतर्गत आने वाले महाविद्यालयों में अनेक गंभीर समस्याएं व्याप्त हैं, जिन पर त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है। उन्होंने झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुसार 60 वर्ष से अधिक आयु के शिक्षकों एवं अधिकारियों को प्रशासनिक पदों से हटाने की मांग की। साथ ही परीक्षा नियंत्रक पर लगे आरोपों की निष्पक्ष जांच कर उन्हें पदमुक्त करने, कुलाधिपति के आदेशानुसार ओएसडी को हटाने तथा गंभीर आरोपों से घिरे अधिकारियों को प्रशासनिक दायित्वों से मुक्त करने की मांग उठाई।

प्रदर्शन के दौरान अभाविप ने 'छात्र सहायता केंद्र' की स्थापना, विश्वविद्यालय बस सेवा शुरू करने, एनएसएस से संबंधित वर्ष 2022 से 2026 तक के भुगतानों की जांच तथा एनसीसीएफ को किए गए भुगतानों की पारदर्शी जांच कराने तथा विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव शीघ्र कराने एवं परीक्षा विभाग की निष्पक्ष जांच की मांग भी उठाई। विभाग संगठन मंत्री हिमांशु दुबे ने कहा कि भ्रष्टाचार में संलिप्त दोषियों के विरुद्ध उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कर्मचारियों द्वारा छात्रों के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार पर रोक लगाने, निर्माणाधीन छात्रावास को शीघ्र पूरा कर शुरू करने तथा विश्वविद्यालय में चल रहे भवन निर्माण कार्यों की गुणवत्ता जांच कराने एवं परीक्षाओं एवं परिणामों को समयबद्ध तरीके से घोषित करने और उच्च शिक्षा के छात्रों की लंबित फाइलों के शीघ्र निष्पादन की भी मांग की।

प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अमन शाह ने कहा कि खेल शुल्क लेने के बावजूद छात्रों को खेल सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। उन्होंने सभी महाविद्यालयों में पेयजल, स्वच्छता एवं सुरक्षा गार्ड की समुचित व्यवस्था की मांग की। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

नेतृत्व विकास का सशक्त माध्यम बनी छात्रा संसद

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) छत्तीसगढ़ प्रांत द्वारा राजधानी रायपुर स्थित पुराने विधानसभा भवन में 'प्रांत छात्रा संसद-2026' का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के 27 जिलों से आई 227 छात्राओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और भारतीय चिंतन में महिलाओं की भूमिका जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। आयोजन से पहले छात्राओं ने अपने-अपने क्षेत्रों में सर्वेक्षण करके शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वावलंबन से जुड़ी समस्याओं का अध्ययन किया और अध्ययन से जुड़े तथ्यों को छात्रा संसद में सामने रखा।

वीरांगना रानी अबक्का चौटा को समर्पित छात्रा संसद-2026 के उद्घाटन सत्र की मुख्य अतिथि एवं छत्तीसगढ़ सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बेटियों की भूमिका को सामने रखते हुए कहा कि वर्तमान में हर क्षेत्र में बेटियां अपनी क्षमता सिद्ध करते हुए देश के नेतृत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। छात्रा संसद में क्षेत्रीय छात्रा प्रमुख शालिनी वर्मा, केंद्रीय कार्यसमिति सदस्य राशि त्रिवेदी तथा प्रांत मंत्री अनंत सोनी सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। सभी वक्ताओं ने छात्राओं को सामाजिक जिम्मेदारी, आत्मनिर्भरता और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया।

छात्रा संसद के पहले सत्र में प्रशासनिक अधिकारी वैभवी अग्रवाल ने शिक्षा को व्यक्तित्व निर्माण की आधारशिला बताते हुए बालिकाओं तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने की आवश्यकता पर बल दिया। डा. वर्णिका शर्मा ने छात्राओं को आत्मनिर्भर बनने और अपनी क्षमताओं को पहचानने के लिए प्रेरित किया। दूसरे सत्र में स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विषयों पर डा. गुलाटी ने संतुलित जीवनशैली, पौष्टिक आहार और मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को और रचना नायडू ने छात्राओं को कानूनी जागरूकता, सामाजिक सुरक्षा और महिला अधिकारों के प्रति सजग रहने का संदेश दिया।

छात्रा संसद के समापन सत्र में अभाविप के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डा. आशुतोष मांडवी तथा प्रांत संगठन मंत्री महेश साकेत ने छात्राओं की सक्रिय भागीदारी की सराहना करते हुए कहा कि छात्रा संसद समाज परिवर्तन और नेतृत्व विकास का सशक्त माध्यम बन रही है। संसद में हिस्सा लेने वाली छात्राओं ने इसे प्रेरणादायी और जीवन बदलने वाला अनुभव बताया। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

परमाणु क्षेत्र में बढ़ता स्वदेशीकरण

तमिलनाडु स्थित कल्पक्कम में बने स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (पीएफबीआर) ने पहली बार सफलतापूर्वक 'क्रिटिकलिटी' हासिल कर ली है अर्थात रिएक्टर में परमाणु विखंडन श्रृंखला प्रतिक्रिया (एफसीआर) नियंत्रित रूप से आरम्भ हो चुकी है। इस स्थिति में प्रत्येक परमाणु विखंडन से निकलने वाले न्यूट्रॉन अगली प्रतिक्रिया को जारी रखने के लिए पर्याप्त होते हैं, जिससे एक स्थिर ऊर्जा उत्पादन शुरू होता है। परमाणु ऊर्जा के स्वदेशीकरण की दृष्टि से तमिलनाडु स्थित कल्पक्कम में मिली इस ऐतिहासिक सफलता के बाद भारत विश्व में (रूस के बाद) दूसरा ऐसा देश बन गया है, जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का व्यावसायिक संचालन करेगा।

जानकारी के अनुसार भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में पांच सौ मेगावाट क्षमता वाले प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (पीएफबीआर) ने गत 6 अप्रैल को सफलतापूर्वक प्रथम क्रिटिकैलिटी प्राप्त की, जो नियंत्रित परमाणु विखंडन श्रृंखला प्रतिक्रिया की शुरुआत का प्रतीक है। यह उपलब्धि भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और स्वदेशी परमाणु प्रौद्योगिकी क्षमताओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह उपलब्धि सभी निर्धारित सुरक्षा आवश्यकताओं के सफल समापन के बाद प्राप्त हुई है, जिसे परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी) द्वारा गहन समीक्षा के बाद स्वीकृत किया गया।

स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र (आईजीसीएआर) द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है, जो परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत एक प्रमुख अनुसंधान एवं विकास संस्थान है। रिएक्टर का निर्माण और संचालन भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड (भविनी) द्वारा किया गया, जो परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर भारत की दीर्घकालिक परमाणु रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और पारंपरिक थर्मल रिएक्टरों के विपरीत यह यूरेनियम-प्लूटोनियम मिक्स्ड ऑक्साइड (एमओएक्स) ईंधन का उपयोग करता है। प्रथम चरण की महत्वपूर्णता प्राप्त करने के साथ भारत अपने तीन-चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की पूर्ण क्षमता को साकार करने के करीब पहुंच गया है। यह उपलब्धि उन असंख्य वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, तकनीशियनों और उद्योग भागीदारों के समर्पित प्रयासों को दर्शाती है, जिन्होंने मुख्यतः स्वदेशी तकनीकों और घटकों का उपयोग करते हुए रिएक्टर के डिजाइन, निर्माण और संरचना में योगदान दिया। यह उन्नत परमाणु अभियांत्रिकी में भारत की बढ़ती विशेषज्ञता और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के अंतर्गत तकनीकी आत्मनिर्भरता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करता है।

उधर समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा को और दृढ़ करने के लिए भारत ने परमाणु ऊर्जा संचालित तीसरी बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी आईएनएस अरिदमन को नौसेना के बेड़े में शामिल कर लिया है। अरिहंत श्रेणी के अंतर्गत स्वदेशी रूप से विकसित आईएनएस अरिदमन 83 मेगावाट के स्वदेशी परमाणु रिएक्टर से संचालित किया जाएगा। आईएनएस अरिहंत (2016) और आईएनएस अरिघात (2024) के बाद आईएनएस अरिदमन अब नौसेना की ताकत को और सशक्त करेगा। गत 3 अप्रैल को नौसेना के बेड़े में शामिल एवं पारंपरिक रूप से संचालित हमलावर पनडुब्बियों की तुलना में गुप्त, धीमी गति से चलने वाली और गहराई में अधिक गुप्त होने में सक्षम सात हजार टन वजन वाली आईएनएस अरिदमन पनडुब्बी 3,500 किलोमीटर तक मार करने वाली के-4 मिसाइलों से लैस है, जो समुद्र से परमाणु हमला करने की क्षमता को मजबूत करती है। विशाखापट्टनम स्थित शिप बिल्डिंग सेंटर में 'एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वेसल' प्रोजेक्ट के तहत विकसित आईएनएस अरिदमन 90 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी है। यह पनडुब्बी समुद्र की गहराई में छिपकर किसी भी वक्त दुश्मन पर जवाबी परमाणु हमला करने में सक्षम है। इसी के साथ भारत विश्व के उन देशों की लिस्ट में शामिल है, जिनके पास परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां हैं। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

सुरक्षा एवं रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण ग्रेट निकोबार परियोजना

■ संजय दीक्षित

भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा एवं भविष्य आधारित समुद्री रणनीति को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार महत्वाकांक्षी ग्रेट निकोबार अधोसंरचना परियोजना पर काम कर रही है। राष्ट्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण यह परियोजना एक ऐसी रणनीतिक परियोजना भी है, जिसका उद्देश्य अंडमान सागर और दक्षिण-पूर्व एशिया में भारत की उपस्थिति को सशक्त करना है। साथ ही यह परियोजना केंद्र सरकार की उस बुनियादी ढांचा पहल का भी हिस्सा है, जिसका उद्देश्य पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील द्वीप को एक प्रमुख समुद्री और आर्थिक केंद्र में परिवर्तित करना है। भू-रणनीतिक आवश्यकताओं, सुरक्षा संबंधी चिंताओं एवं आर्थिक पुनरुद्धार पर केंद्रित परियोजना की परिकल्पना 2021 में नीति आयोग ने की थी। परियोजना का कार्यान्वयन अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह एकीकृत विकास निगम द्वारा किया जाना है। केंद्र सरकार के अमृत काल विजन-2047 के अंतर्गत प्रमुख परियोजनाओं में से एक ग्रेट निकोबार परियोजना के माध्यम से हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री और हवाई संपर्क का एक ऐसा केंद्र बनाना है, जो सामरिक एवं रणनीतिक दृष्टि से भारत की शक्ति को और सशक्त बनाने का काम करेगा।

क्या है ग्रेट निकोबार परियोजना?

राष्ट्रीय महत्व वाली ग्रेट-निकोबार परियोजना का क्रियान्वयन अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी द्वीप ग्रेट निकोबार में होना है, जिसकी लागत लगभग 92,000 करोड़ रुपए है। परियोजना के अंतर्गत ग्रेट निकोबार द्वीप को रणनीतिक एवं आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित करते हुए यहां परिवहनकेन्द्रित बंदरगाह, एकीकृत नगर, नागरिक एवं सैन्य उपयोग वाला हवाईअड्डा, गैस एवं सोलर पावर प्लांट का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए ग्रेट निकोबार में लगभग 166.10 वर्ग किलोमीटर भूमि का अधिग्रहण किया गया है, जिसमें 130.75 वर्ग किलोमीटर वन भूमि भी शामिल है।

सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार हिंद महासागर की सुरक्षा एवं व्यापारिक मार्गों (मलक्का जलडमरू मध्य के निकट) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण एवं तीन चरणों में पूरी होने वाली ग्रेट निकोबार परियोजना को सुनियोजित रूप से विवादित बनाने की चेष्टा लम्बे समय से की जा रही है। कारण यह है कि हिन्द महासागर क्षेत्र में भारत की बढ़ती शक्ति कई देशों के लिए बड़ी चिंता का कारण बन गई है। चूंकि ग्रेट निकोबार परियोजना से अंडमान सागर और दक्षिण-पूर्व एशिया में भारत की शक्ति और मजबूत होगी, इसीलिए भारत के सामरिक एवं आर्थिक विकास को रोकने के लिए परियोजना का सुनियोजित रूप से विरोध किया जा रहा है।

रामायण कालीन अंडमान-निकोबार

राष्ट्रीय सुरक्षा, समुद्री रणनीति और आर्थिक विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण अंडमान-निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में दक्षिण-पूर्व स्थित भारत का वह केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें लगभग 572 छोटे-बड़े द्वीप शामिल हैं। उत्तर में म्यांमार और दक्षिण में इंडोनेशिया (सुमात्रा) के निकट स्थित अंडमान-निकोबार द्वीप समूह सदियों से भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। ऐतिहासिक दृष्टि से यहां का इतिहास रामायण काल से जुड़ा हुआ है और रामायण काल में द्वीप का नाम 'हण्डुकमान' था। चोल वंश के समय भी अंडमान-निकोबार द्वीप समूह एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा। लेखक एस. के. नारंग ने अपनी पुस्तक 'काले पानी की कलंक कथा' में बताया है कि 'निकोबार' नाम का सबसे पहला संदर्भ श्रीलंकाई पाली बौद्ध कालक्रम में, दिपवासा (तीसरी और चौथी शताब्दी ईस्वी) और महावामा (चौथी और पांचवीं शताब्दी ईस्वी) में मिलता है। तमिल चोल वंश के राजाओं में से एक चोल राजा, राजेंद्र-प्रथम (1014-1042) ने कार-निकोबार और ग्रेट-निकोबार को जीतने के बाद एक

रणनीतिक नौ-सैनिक आधार के रूप में उपयोग किया। रामायण काल से उल्लिखित यह द्वीप समूह डेनमार्क, ब्रिटेन एवं जापान के नियंत्रण में भी रहा। सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा 'आजाद हिंद सरकार' की स्थापना किए जाने के बाद 6 नवंबर 1943 को जापान ने अंडमान-निकोबार द्वीप समूह पर अपना कब्जा छोड़ दिया और द्वीप को आजाद हिन्द सरकार को सौंप दिया। नेताजी ने 30 दिसंबर 1943 को पोर्ट ब्लेयर में पहली बार स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज (तिरंगा) फहराया और फिर अंडमान द्वीप का नाम 'शहीद' तथा निकोबार का नाम 'स्वराज' रखा।

रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण परियोजना

रणनीतिक रूप से ग्रेट-निकोबार द्वीप परियोजना को अत्यंत संवेदनशील कहा जा सकता है। इससे अंडमान सागर और दक्षिण-पूर्व एशिया में भारत की उपस्थिति मजबूत होने के साथ ही समुद्री एवं रक्षा क्षमता में बढ़ोत्तरी होगी। परियोजना के माध्यम से भारत, हिंद महासागर और दक्षिण-पूर्व एशिया में अपनी नौसैनिक उपस्थिति बढ़ाने और क्षेत्र में किसी भी गतिविधि पर निगरानी के लिए पूर्ण रूप से सक्षम होगा, जिससे भारत की समुद्री सीमाओं को नई मजबूती मिल सकेगी। ग्रेट निकोबार परियोजना को चीन की 'मोतियों की माला' अर्थात 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' रणनीति के जवाब के रूप में देखा जा सकता है। गत दो दशक के दौरान हिंद महासागर क्षेत्र में चीन ने बंदरगाहों एवं नौसेना ठिकानों का एक जाल बनाया है, जिसमें पाकिस्तान स्थित ग्वादर, श्रीलंका स्थित हंबनटोटा, म्यांमार स्थित क्यौकप्यू और जिबूती में बना एक सैन्य अड्डा शामिल है। चीन की इस रणनीति के प्रत्युत्तर में भारत भी अपने ढंग से सशक्त कदम उठा रहा है और ग्रेट निकोबार परियोजना भी इसी कड़ी का हिस्सा है। सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार परियोजना के कारण असहज चीन की मलक्का स्ट्रेट पर चिंता बढ़ती जा रही है। चीन के लिए मलक्का स्ट्रेट महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विश्व का वह सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है, जिसे चीन के समुद्री व्यापार की जीवनरेखा के रूप में देखा जाता है। यह संकरा समुद्री मार्ग चीन के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाहों को मध्य-पूर्व और अफ्रीका से जोड़ने वाला सबसे छोटा समुद्री मार्ग है। चीन अपने अधिकांश व्यापारिक निर्यात एवं ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसी समुद्री मार्ग पर निर्भर है। विशेषज्ञों के अनुसार सामरिक दृष्टि से भारत भले ही कानूनी रूप से मलक्का स्ट्रेट मार्ग को अवरुद्ध नहीं कर सकता, लेकिन सघन निगरानी और समुद्री संचालन की क्षमता भारत के किसी भी दुश्मन के लिए रणनीतिक अनिश्चितता और जोखिम को बढ़ा सकती है, जो संकट काल में यह बड़ा सामरिक हथियार बन सकता है। इसीलिए हिंद महासागर क्षेत्र में परियोजना को चीन अपने प्रभाव के लिए सीधी चुनौती के रूप में देख रहा है।

आर्थिक दृष्टि से लाभकारी

भारत के लिए ग्रेट निकोबार परियोजना आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वर्तमान समय में समुद्री मार्ग से माल ढुलाई के लिए भारत की निर्भरता विदेशी बंदरगाहों पर अधिक है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत का लगभग 75 प्रतिशत माल संचालन विदेशों में होता है, जिससे आर्थिक रूप से प्रति वर्ष लगभग 22 करोड़ डालर की अनुमानित प्रत्यक्ष हानि हो रही है। ऐसे में ग्रेट निकोबार परियोजना के माध्यम से भारत का लक्ष्य समुद्री परिवहन से होने वाली माल ढुलाई के एक बड़े हिस्से को देश में लाना है, जिससे कोलंबो और सिंगापुर जैसे विदेशी बंदरगाहों पर निर्भरता कम होगी और राजस्व में बढ़ोत्तरी के साथ ही हजारों की संख्या में नए रोजगार का सृजन भी होगा। जानकारी के अनुसार ग्रेट निकोबार परियोजना में बनने वाला बंदरगाह प्राकृतिक तौर पर बीस मीटर से गहरे जलस्तर के साथ बड़े कंटेनर जहाजों के लिए उपयुक्त होगा। इससे बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के बाजारों से निकोबार द्वीप की निकटता बढ़ेगी और यहां से कंटेनर संचालन, ईंधन आपूर्ति, जहाज मरम्मत, भंडारण और विमानन सेवाओं का भी विस्तार होगा, जो पर्यटन सहित अन्य वैश्विक व्यापारिक गतिविधियों को नई गति प्रदान करेगा।

पर्यावरण और दावे

ग्रेट निकोबार परियोजना को लेकर पर्यावरण को होने वाली कथित हानि को लेकर किए जाने वाले दावों से ऐसा प्रचारित किया जा रहा है कि इससे बड़े पैमाने पर पारिस्थितिकी अर्थात पेड़, पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव और उनके जैविक-अजैविक घटकों को व्यापक क्षति होगी, जिसका नकारात्मक प्रभाव पूरे द्वीप पर पड़ेगा। लेकिन पर्यावरण हानि के संबंध में किए जा रहे दावों का कोई तार्किक आधार दिखाई नहीं देता।

जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने संभावित द्वीप समूह के पारिस्थितिक प्रभावों की व्यापक पहचान एवं मूल्यांकन के बाद परियोजना क्रियान्वयन में एक

सुदृढ़ पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रक्रिया और विस्तृत पर्यावरण प्रबंधन योजना को शामिल किया है। इनमें जैव विविधता संरक्षण योजनाएं, प्रवाल संरक्षण और स्थानांतरण, वन्यजीव प्रबंधन रणनीतियां और दीर्घकालिक पारिस्थितिक निगरानी जैसे उपायों को देखा जा सकता है। जानकारों के अनुसार विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन कर तैयार की गई परियोजना में प्रदूषण नियंत्रण, जैव विविधता संरक्षण, और शोंपेन एवं निकोबारी समुदायों के कल्याण की निगरानी के लिए तीन स्वतंत्र निगरानी समितियों का गठन किया गया है। यह समितियां निरीक्षण, निगरानी और अंतर-संस्थागत समन्वय के लिए एक केंद्रीय तंत्र के रूप में कार्य करेगी।

वन पारिस्थितिकी तंत्र पर विशेष जोर

परियोजना क्रियान्वयन के लिए ग्रेट निकोबार द्वीप क्षेत्र का केवल 166.1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है, जो अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के कुल क्षेत्रफल का लगभग दो प्रतिशत है। परियोजना के लिए 130.75 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में परिवर्तन किया जाना है, जो अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के कुल वन क्षेत्र का मात्र लगभग 1.82 प्रतिशत है। इसी तरह परिवर्तित किए जाने वाले 130.75 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में वृक्षों की अनुमानित संख्या 18.65 लाख है, जिसमें से 49.86 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में अधिकतम अनुमानित 7.11 लाख वृक्षों की कटाई भी चरणबद्ध ढंग से 2025 से लेकर 2047 के मध्य की जानी है। परियोजना में 65.99 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को हरित क्षेत्र के रूप में बनाए रखने का निर्णय लिया गया है, जहां एक भी वृक्ष को काटा नहीं जाएगा। परियोजना में 65.99 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को ग्रीन जोन के रूप में सुरक्षित रखा जाएगा। ऐसे में परियोजना को पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक नहीं, बल्कि यह पर्यावरणीय चिंताओं को राष्ट्रीय हितों के साथ संतुलित करने वाली एक सुविचारित पहल कहा जा सकता है।

जनजातीय कल्याण एवं सामाजिक सरोकार

ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में दो प्रमुख जनजातियां निवास करती हैं। इनमें से एक शोंपेन जनजाति है, जो मुख्य रूप से शिकार और संग्राहक हैं। इनके साथ यहां निकोबारी जनजाति के लोग भी रहते हैं, जो तटीय बस्तियों में रहकर अपनी आजीविका के लिए मुख्य रूप से मछली पकड़ने पर निर्भर हैं। जनजातियों के निवास के कारण परियोजना की रूपरेखा अत्यंत संवेदनशीलता के साथ तैयार की गई है, जिससे निकोबारी और शोंपेन जनजाति के लोगों को अपने मूल स्थान से विस्थापित नहीं होना पड़ेगा। यही कारण है कि परियोजना में स्थानीय जनजातीय लोगों के पुनर्वास या विस्थापन संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है।

जनजातीय हितों की सुरक्षा के लिए परियोजना में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा एक 'स्वतंत्र निगरानी समिति' का गठन किया जाना अनिवार्य किया गया है। यह समिति निर्माण और संचालन, दोनों चरणों के दौरान शोंपेन और निकोबारी जनजाति को प्रभावित करने वाले विषयों की कड़ी निगरानी करेगी। वर्तमान में ग्रेट निकोबार द्वीप का 751.070 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आधिकारिक रूप से 'जनजातीय आरक्षित क्षेत्र' के रूप में चिन्हित है।

विकास परियोजनाओं के लिए प्रस्तावित कुल 166.10 वर्ग किलोमीटर भूमि में से 84.10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जनजातीय आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हालांकि इस हिस्से में से 11.032 वर्ग किलोमीटर भूमि का 1972 से ही नियमितीकरण किया जा चुका है और इसे 'राजस्व भूमि' के रूप में उपयोग किया जा रहा है। समग्र रूप से परियोजना में विकास, पर्यावरण एवं सांस्कृतिक संरक्षण के बीच पूर्ण रूप से सामंजस्य स्थापित किया गया है, लेकिन जनजातीय समाज से सम्बंधित भ्रामक एवं गलत जानकारियों के आधार पर विवाद फैलाने की कुचेष्टा लगातार की जा रही है।

आदर्श संतुलन स्थापित करने वाली परियोजना

ग्रेट निकोबार परियोजना को एक ऐसे उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में भी देखा जा सकता है, जो समग्र विकास के माध्यम से आर्थिक प्रगति, पर्यावरणीय संरक्षण और सामाजिक समावेश के बीच एक आदर्श संतुलन स्थापित करती है। वन्यजीव संरक्षण, वन क्षेत्र में होने वाली क्षति की भरपाई, आपदा प्रबंधन की तैयारी और सामाजिक समावेश के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के माध्यम से परियोजना यह भी स्पष्ट करती है कि विकास का मार्ग पर्यावरण की कीमत पर नहीं, बल्कि उसके साथ समन्वय बिठाकर प्रशस्त किया जा सकता है। ऐसे में विकास, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक-दूसरे के पूरक बन सकते हैं, जिससे राष्ट्रीय और वैश्विक हितों की सर्वोत्तम सेवा एवं सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। ■

समाज को दिशा प्रदान करती है कला

राष्ट्रीय कला मंच एवं काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से काशी कला कुंभ-2026 आयोजन किया गया। दो दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव में देश के अलग -अलग हिस्सों से आए कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया।

उत्तर प्रदेश स्थित **वाराणसी** में काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर के पंडित ओंकारनाथ प्रेक्षागृह में गत 22 अप्रैल को आरंभ हुए काशी कला महोत्सव-2026 के उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि एवं उत्तर-पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से जुड़ी अपनी स्मृतियों को साझा करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन प्रतिभाओं को निखारने का सजीव मंच प्रदान करते हैं। कला और संगीत की गहराई को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय समाज की जड़ों में ही संगीत और कला रची-बसी है। उन्होंने काशी को स्वयं में एक 'कला कुंभ' बताते हुए सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दीं।

उद्घाटन सत्र में डा. अपराजिता मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक 'वेदकालीन आध्यात्मिक महिलाएं' का विमोचन भी किया गया। इस अवसर पर महोत्सव कार्यक्रम की अध्यक्ष डा. मधुमिता भट्टाचार्य ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम निरंतर होते रहने चाहिए, जिससे न केवल कला के विविध आयामों को मंच मिलता है, बल्कि आयोजनों की रूपरेखा और गुणवत्ता भी निरंतर विकसित होती है। राष्ट्रीय कला मंच के अखिल भारतीय प्रमुख अंकित शुक्ला ने राष्ट्रीय कला मंच के औचित्य और वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता पर प्रकाश डालते हुए मंच द्वारा संचालित विभिन्न प्रकल्पों की जानकारी दी और युवाओं को इसमें सक्रिय सहभागिता के लिए प्रेरित किया। पूर्व सह क्षेत्रीय संगठन मंत्री एवं महोत्सव के विशिष्ट अतिथि आनंद श्रीवास्तव ने कला के वैश्विक प्रभावों को रेखांकित करते हुए कहा कि लोक कलाओं के माध्यम से अभिव्यक्त होने वाली भावनाएं समाज के स्वरूप को स्पंदित करती हैं और उनमें नवनिर्माण का सशक्त संदेश निहित होता है। प्रसिद्ध कथावाचक पलक किशोरी के अनुसार भारतीय ज्ञान परंपरा 'अनहद नाद' के समान है, जो निरंतर प्रवाहित होती रहती है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वर्तमान समय उनके लिए

अपनी क्षमताओं के विस्तार का सर्वोत्तम अवसर है। रा. स्व. संघ काशी प्रांत प्रचारक रमेश ने कहा कि प्रकृति के प्रत्येक सजीव तत्व में कला विद्यमान है और यह व्यक्ति के जीवन के साथ-साथ समाज निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज आवश्यकता है कि स्क्रीन टाइम को कम कर रचनात्मक और कलात्मक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए। प्रदेश ललित कला अकादमी के अध्यक्ष सुनील विश्वकर्मा के अनुसार कला चारों पुरुषार्थों की पूर्ति करती है और कल्याणकारी रूप में समाज को दिशा प्रदान करती है।

महोत्सव के पहले दिन आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में देश के विभिन्न हिस्सों से आए कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से वातावरण को झंकृत कर दिया। अयोध्या एवं ग्वालियर घराने से कला कुंभ में आए संगीतज्ञों ने वाद्य यंत्रों पर धुन-श्रृंगार से कार्यक्रम के सौंदर्य को बहुगुणित कर दिया।

महोत्सव के दूसरे एवं अंतिम दिन उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह ने काशी को कला की राजधानी बताते हुए कहा कि काशी ने विभिन्न कला क्षेत्रों में अनेक महान व्यक्तियों को जन्म दिया है, जिससे भारतीय संस्कृति समृद्ध हुई है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि देश के लोगों को बाहरी संस्कृति को अपनाने से पहले अपनी समृद्ध भारतीय संस्कृति को समझना और अपनाना चाहिए।

समापन अवसर पर अभाविप के क्षेत्रीय संगठन मंत्री घनश्याम शाही ने कहा कि राष्ट्रीय कला मंच नवोदित कलाकारों को मंच प्रदान करने का एक सार्थक प्रयास है। उन्होंने कला को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देते हुए युवा प्रतिभाओं के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। भोजपुरी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता मनोज सिंह 'टाइगर' ने भोजपुरी सिनेमा के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डालते हुए युवाओं को अपनी प्रतिभा को निरंतर निखारने और कला के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। समापन समारोह में मंच कला संकाय की प्रमुख डा. संगीता पंडित, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र अधिष्ठाता प्रो. रंजन सिंह, अभाविप बीएचयू इकाई अध्यक्ष पल्लव सुमन ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए।

समापन समारोह के दौरान प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों में संगीत, नृत्य एवं लोक कलाओं की सजीव प्रस्तुतियों ने काशी की सांस्कृतिक आत्मा को साकार कर दिया। अंत में प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया।

डुग्गर सांस्कृतिक संगम

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) जम्मू-कश्मीर एवं राष्ट्रीय कला मंच के संयुक्त तत्वावधान में गत 26 अप्रैल को **रामबन** जिले के एमबी पैलेस में डुग्गर सांस्कृतिक संगम का आयोजन किया गया। सांस्कृतिक संगम में दस जिलों से आए कलाकारों ने डुग्गर क्षेत्र की लोककला, संस्कृति और पारंपरिक विरासत की मनोहारी प्रस्तुतियां दीं।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पद्मश्री से सम्मानित रुमालू राम, विशिष्ट अतिथि के रूप में जम्मू संभाग के स्कूल शिक्षा निदेशक गुरुदेव कुमार सराजी और रामबन के अतिरिक्त उपायुक्त वरुणजीत सिंह चडक उपस्थित रहे। अभाविप राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य एवं विकसित भारत-2047 की राष्ट्रीय युवा आइकॉन त्रिप्ति सैनी ने विशिष्ट अतिथि के रूप में हिस्सा लिया।

डुग्गर सांस्कृतिक संगम में ढोल वादन, बांसुरी वादन, थाली नृत्य, रणशिंगा वादन, साफा बांधना, जोड़ी और भाख जैसी डुग्गर संस्कृति की पारंपरिक लोककलाओं को प्रस्तुत किया गया। कलाकारों के उत्साह और पारंपरिक वेशभूषा ने पूरे माहौल को सांस्कृतिक रंगों से भर दिया। बाद में डुग्गर संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 58 कलाकारों को सम्मानित किया गया। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

National Symposium Highlights One Health Approach for Rural Resilience

The 2nd National Veterinary, Dairy & Fisheries Symposium–2026 concluded successfully at Nagpur Veterinary College after two days of intensive discussions, expert lectures and policy deliberations on strengthening India's veterinary, dairy and fisheries sectors through the 'Integrated One Health Approach.'

The symposium was jointly organised by Agrivision in collaboration with Maharashtra Animal and Fisheries Sciences University (MAFSU), Veterinary Council of India (VCI), National Fisheries Development Board (NFDB) and Vidyanidhi Nagpur. Held on April 11-12, the event brought together academicians, policymakers, researchers, students and industry representatives from more than 20 states.

The inaugural session was attended by Union Minister of State for Animal Husbandry, Dairy and Fisheries S. P. Singh Baghel as Chief Guest. Other prominent dignitaries included Dr. Niteen Patil, Vice Chancellor of MAFSU; Devdatt Joshi, National Joint Organising Secretary of ABVP; Dr. Umesh Sharma, President of VCI and Dr. B. K. Behera, Chairman of NFDB.

Addressing the gathering, Shri Baghel emphasised the need for modern reproductive technologies such as sex-sorted semen and IVF-based embryo transfer to improve livestock productivity and enhance farmers' income. Organising Secretary Dr. Shirish Upadhyay introduced the objectives of the symposium, while Agrivision National Convenor Manish Fate highlighted the organisation's initiatives in rural and agricultural development.

The technical sessions focused on the practical implementation of the One Health concept, emphasising the interconnection between animal, human and environmental health. Experts including Dr. P. K. Pandey, Dr. S. B. Barbuddhe, Sudhir Kumar Singh and

Dr. Rajesh Gupta discussed interdisciplinary collaboration and future opportunities in India's dairy and livestock sectors. A special lecture on 'Viksit Bharat Ki Sankalpana' by Devdatt Joshi inspired students to contribute actively toward nation-building and national development.

Separate sector-wise sessions on Veterinary, Dairy and Fisheries provided specialised platforms for detailed discussions. The Fisheries session highlighted aquaculture entrepreneurship, fish health management and climate resilience. The Dairy session focused on dairy value chains, innovations in milk production and entrepreneurship opportunities for rural livelihoods. Veterinary experts deliberated on disease management, biosecurity and advancements in diagnostics and treatment under the One Health framework.

On the second day, the Resolution Session discussed five major proposals aimed at strengthening education, research, policy implementation and timely conduct of ASRB examinations in allied agricultural sectors. The resolutions were formally adopted after interaction with student delegates.

The symposium also featured a Role Model Session where speakers including Dr. Dhiraj Mankari, Dr. Abhijeet Naohate, Shraddha Dhawan and Dr. Nina Singh shared experiences related to agribusiness, dairy entrepreneurship, aquaculture startups and innovative livestock management. The session encouraged students to explore self-employment and startup opportunities. Technical Session-II included expert lectures on poultry enterprises, sustainable livestock development and One Health initiatives by Dr. Sunil Garg, Dr. Manoj Aware and Dr. Jogdand Swati.

The valedictory session was graced by Padma Shri awardee Dr. Punyamurti as Chief Guest. He emphasised dedication, innovation and service in agriculture and allied sectors. Awards for Best Poster Presentations were distributed to participants for outstanding research contributions.

According to organisers, the symposium witnessed participation from 20 states, 25 universities and 46 colleges. A total of 365 participants attended the event, including 279 undergraduate students, 55 postgraduate students and 31 professors. Participation also included 1 Union Minister, 3 Vice Chancellors, 7 Deans and 36 technical speakers.

Field-wise participation comprised 249 delegates from Veterinary Sciences, 86 from Fisheries and 30 from Dairy Sciences. The overall event strength, including volunteers, organisers, and state convenors, reached 532 attendees.

Organisers described the symposium as a major national platform for promoting collaboration, innovation, entrepreneurship and policy dialogue in the veterinary, dairy and fisheries sectors while strengthening India's rural resilience through the One Health approach. ■

(Rashtrsiya Chhatrashakti Team)

एनसीईआरटी को मिला 'डीम्ड विश्वविद्यालय' का दर्जा

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) को 'डीम्ड विश्वविद्यालय' का दर्जा दे दिया है। अब एनसीईआरटी भी अन्य विश्वविद्यालय की तरह कार्य करने के लिए स्वतन्त्र होगी, लेकिन इसके साथ ही कई आवश्यक नियमों के अनुपालन की व्यवस्था भी लागू की गई हैं।

जानकारी के अनुसार एनसीईआरटी ने यूजीसी अधिनियम-1956 की धारा-3 के अंतर्गत डीम्ड विश्वविद्यालय बनने के लिए आवेदन किया था। 'डीम्ड विश्वविद्यालय' का दर्जा हासिल करने के लिए एनसीईआरटी ने सभी आवश्यक शर्तों को पूरा करते हुए अपनी रिपोर्ट 2025 में केंद्र सरकार को दी। विशेषज्ञ समिति द्वारा की जांच में रिपोर्ट को सही पाए जाने के बाद यूजीसी आयोग ने इसी वर्ष जनवरी माह में हुई अपनी बैठक में प्रस्ताव को स्वीकृत दी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने अपनी स्वीकृति प्रदान की।

डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा हासिल करने के लिए एनसीईआरटी के छह प्रमुख संस्थानों को शामिल किया गया है। इन सभी संस्थानों को मिलाकर एनसीईआरटी को एक विशेष श्रेणी में विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। केंद्र सरकार ने एनसीईआरटी को कुछ सख्त नियमों का अनुपालन करने के लिए कहा है, जिसमें एनसीईआरटी से जुड़े संस्थान अपनी संपत्ति या फंड बिना सरकार और यूजीसी की अनुमति के स्थान्तरित नहीं करने एवं किसी भी तरह की लाभ कमाने वाली गतिविधि में शामिल न होने का नियम शामिल है। इसके साथ ही एनसीईआरटी को अपने सभी पाठ्यक्रम यूजीसी और अन्य शिक्षा संस्थाओं के नियमों के अनुसार ही चलाने होंगे। नए पाठ्यक्रम, ऑफ-कैंपस सेंटर या विदेशी कैंपस भी निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही आरम्भ किए जा सकेंगे। छात्रों के प्रवेश, सीटों की संख्या और फीस से सम्बंधित अन्य सभी नियमों का पालन करना भी आवश्यक होगा। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

। उत्तर प्रदेश ।

अमर्यादित शिक्षक के विरुद्ध कार्रवाई का अभाविप ने किया स्वागत

लखनऊ विश्वविद्यालय में विज्ञान विभाग की छात्रा के साथ सहायक आचार्य परमजीत सिंह द्वारा फोन पर की गई अमर्यादित, भद्दी और शिक्षक की गरिमा को कलंकित करने वाली वार्ता की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने कड़े शब्दों में निंदा की है। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा मामले में की गई त्वरित कार्रवाई का स्वागत करते हुए अभाविप ने इसे न्यायोचित, आवश्यक एवं संस्थागत जवाबदेही की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। अभाविप का कहना है कि शैक्षणिक परिसर केवल शिक्षा अर्जन ही नहीं, अपितु छात्र-छात्राओं के सर्वांगीण विकास और सुरक्षित वातावरण का केंद्र होना चाहिए, जहां ऐसी ओछी मानसिकता के लिए कोई स्थान नहीं है। अभाविप लखनऊ विश्वविद्यालय इकाई के अध्यक्ष जय श्रीवास्तव के अनुसार एक प्रतिष्ठित संस्थान में गुरु-शिष्य की पवित्र परंपरा को तार-तार करना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और अक्षम्य है। अभाविप ऐसी कुत्सित मानसिकता रखने वाले शिक्षक को अविलंब बर्खास्त करते हुए उनके विरुद्ध तत्काल कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग करती है। साथ ही पीड़ित छात्रा को न्याय दिलाने के लिए अभाविप पूरी दृढ़ता के साथ खड़ी है। इस घिनौने कृत्य के कारण पीड़ित छात्रा मानसिक रूप से अत्यंत प्रताड़ित है एवं अपने ही परिसर में असुरक्षित महसूस कर रही है, जो किसी भी संवेदनशील संस्थान के लिए अत्यंत चिंताजनक विषय है। मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई अभाविप कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए निरंतर संघर्ष, व्यापक प्रदर्शन एवं प्रशासन पर बनाए गए लोकतांत्रिक दबाव का परिणाम है। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

'शाश्वत है प्रा.केलकर प्रदत्त कार्यपद्धति'

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) के संगठन शिल्पी प्रा. यशवंतराव केलकर जन्मशताब्दी वर्ष के समापन अवसर पर देश के कई स्थानों में 'प्रिय केलकर जी' अभिवाचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में यशवंतराव केलकर के जीवन वृतांत को बेहद सुंदर और आकर्षक ढंग से रेत कला (सैंड आर्ट) के जरिए दर्शाया गया।

नागपुर में गत 25 अप्रैल को आयोजित 'प्रिय यशवंतराव' अभिवाचन कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। अभाविप-विदर्भ प्रांत द्वारा कविवर्य सुरेश भट सभागृह में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम हमारे जीवन में प्रा. यशवंतराव केलकर के चिंतन का प्रारंभ करने वाला है। प्रा. केलकर द्वारा प्रदत्त कार्यपद्धति शाश्वत है, जो आज भी समाज एवं राष्ट्र निर्माण के लिए समान रूप से प्रासंगिक है। ज्ञान और कर्म का आधार भक्तिभाव है तथा यही भाव युवाशक्ति को सही दिशा प्रदान करता है। डा. भागवत ने युवाओं का आह्वान किया कि प्रा. केलकर जैसे व्यक्तित्व को आदर्श मानते हुए स्वयं को आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनाएं।

कार्यक्रम में अभाविप के राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष चौहान ने अपने सम्बोधन में कहा कि सशक्त संगठन निर्माण का आधार व्यक्ति निर्माण है, क्योंकि सुदृढ़ व्यक्तित्व ही मजबूत संगठन की आधारशिला होता है। प्रा. यशवंतराव जी ने ज्ञान, शील और एकता के सिद्धांतों पर आधारित जो कार्यपद्धति विकसित की थी, वह आज अभाविप कार्यपद्धति का मूल आधार है। कार्यक्रम में अभाविप विदर्भ प्रांत अध्यक्ष डा. श्रीकांत पर्वत, राष्ट्रीय मंत्री पायल किनाके, प्रांत मंत्री देवाशीष गोतरकर के साथ ही बड़ी संख्या में अभाविप के कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

उधर **राजधानी दिल्ली** में गत 10 मई को आयोजित 'प्रिय केलकर जी' विशेष अभिवाचन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने स्वर्गीय केलकर जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपने उद्बोधन में कहा कि वर्तमान समय में कार्यकर्ताओं के अभ्यास वर्ग में जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं, वह यशवंतराव जी की देन है और उनका जीवन तमाम कार्यकर्ताओं के लिए आदर्श का प्रतिमान है।

छात्र कल्याण न्यास एवं अभाविप-दिल्ली प्रदेश के संयुक्त तत्वावधान में नई दिल्ली स्थित सिविक सेंटर के केदारनाथ साहनी सभागार में आयोजित कार्यक्रम में सर

कार्यवाह होसबाले ने कहा कि यशवंतराव केलकर ही वह पहले व्यक्ति थे, जो अभाविप में महिला सहभागिता, छात्र उपयोगिता के बिंदुओं पर कार्य करने के लिए आगे आए। छात्र आंदोलन के सिद्धांत को कैसे कार्य करना चाहिए?

यह उनके व्यक्तित्व से पता चलता है। वह कहते थे कि अभाविप से प्राप्त गुण को लेकर कार्यकर्ता जब सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन में जाकर सक्रिय होंगे तो वह समाज के उत्थान के लिए अपनी आहुति भी देंगे। केलकर जी के विराट चरित्र को समझने के लिए अध्ययन, चिंतन और मनन की आवश्यकता है।

कार्यक्रम में अभाविप के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज किशोर तिवारी ने कहा कि अभाविप की व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया को पूरे राष्ट्र में समर्थन प्राप्त है, जिसके प्रणेता यशवंतराव केलकर जी थे। अभाविप के विकासक्रम में उनकी महती भूमिका रही। उनसे प्राप्त प्रेरणा बिंदुओं से पुराने और वर्तमान को अवगत कराया जाना चाहिए ताकि कार्यकर्ताओं को एक साथ जोड़ने का काम संभव हो सके।

कार्यक्रम में अभाविप के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार भाटिया ने कहा कि अभाविप में एक खास पद्धति को विकसित करने में यशवंतराव केलकर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। वह अभाविप के संगठन शिल्पी थे और संगठन को नई रूप में ढालने में उन्होंने जीवन भर कार्य किया। अभिवाचन कार्यक्रम में मिलिंद भांगे ने अपने मराठी से हिंदी में रूपांतरित यशवंत राव केलकर पर अभिवाचन प्रस्तुति प्रदर्शित की।

मध्य प्रदेश स्थित जबलपुर में अभाविप-महाकोशल प्रान्त द्वारा आयोजित 'प्रिय केलकर जी' कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव के साथ ही अभाविप के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रा. रघुराज किशोर तिवारी भी उपस्थित रहे।

महाकोशल प्रांत के विभिन्न जिलों से आए कार्यकर्ताओं के बीच मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने कहा कि जिस प्रकार एक पथिक को छांव मिलती है और उसे जो आनंद की अनुभूति होती है, वही आनंद की अनुभूति उन्हें इस कार्यक्रम में आने पर हो रही है। उन्हें प्रा. केलकर जी के साथ काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने विशिष्ट कार्य शैली और पद्धति से अभाविप को विभिन्न आयामों में काम करने के लिए दिशा दी। वास्तव में वह अभाविप की चलती-फिरती पाठशाला थे, जहां से संस्कारी एवं अनुशासित कार्यकर्ता निकलकर समाज और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री यादव ने अपने व्यक्तिगत जीवन में स्वर्गीय केलकर जी से जुड़े कई प्रसंगों को भी साझा किया।

कार्यक्रम में अभाविप के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज किशोर तिवारी सहित अभाविप-मध्य क्षेत्र के क्षेत्रीय संगठन मंत्री चेतस सुखड़िया, प्रांत अध्यक्ष डा. सुनील पांडे, प्रांत मंत्री सुव्रत बजल, प्रांत संगठन मंत्री मनोज यादव, प्रांत सह संगठन मंत्री आशीष शर्मा, केंद्रीय कार्यसमिति सदस्य माखन शर्मा, सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं पूर्व कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गत 27 अप्रैल को आयोजित 'प्रिय केलकर जी' कार्यक्रम में अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री डा. वीरेंद्र सिंह सोलंकी एवं पूर्व प्रदेश संगठन मंत्री हरीश लूनिया उपस्थित रहे। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय (रायपुर) के प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री डा. वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि भारत को पुनः विश्वगुरु बनाने के संकल्प में प्रा. केलकर की कार्यपद्धति का महत्वपूर्ण योगदान है।

उन्होंने 'विद्यार्थी आज का नागरिक है' के मूल विचार को रेखांकित करते हुए कहा कि यह विचार आज भी संगठन के कार्यकर्ताओं को प्रेरणा देता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए समाज में समरसता एवं संगठनात्मक मूल्यों को सशक्त करने का आह्वान किया।

इससे पहले अपने सम्बोधन में हरीश लूनिया ने कहा कि प्रा. केलकर केवल राष्ट्र निर्माण ही नहीं, बल्कि कार्यकर्ता निर्माण के भी सजग शिल्पकार थे। उनकी कार्यशैली एवं पद्धति ने विद्यार्थी परिषद को विभिन्न आयामों में कार्य करने की दिशा प्रदान की। उन्होंने प्रा. केलकर को 'चलती-फिरती पाठशाला' बताते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन से तैयार हुए संस्कारित एवं अनुशासित कार्यकर्ता आज भी समाज एवं राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रहे हैं। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

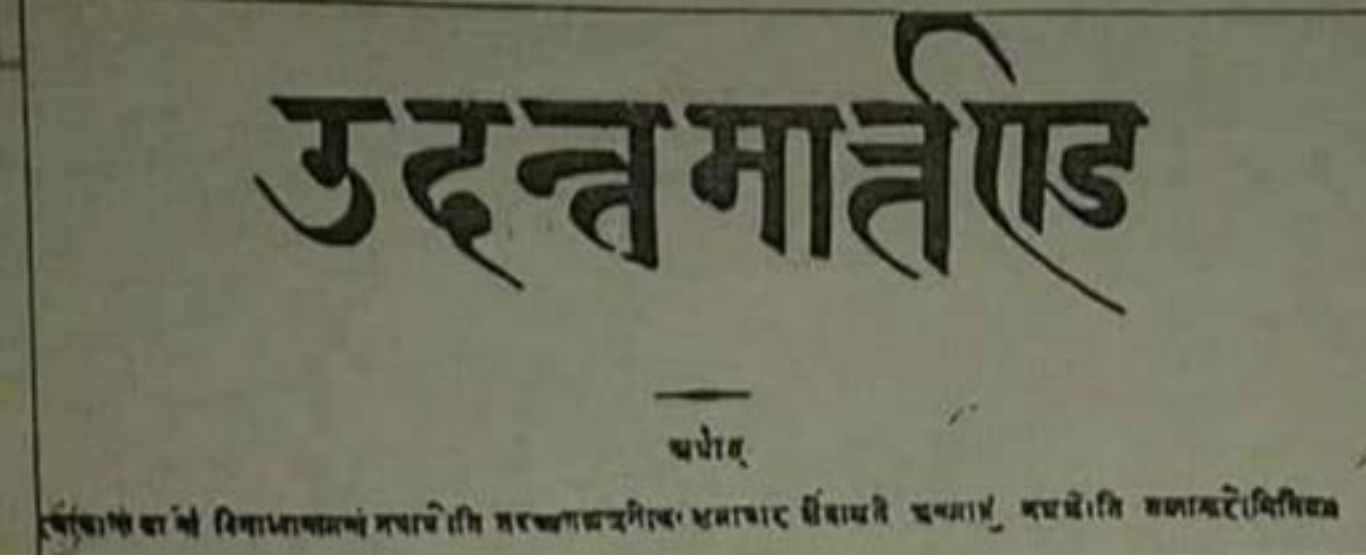

संघर्ष, स्वतंत्रता और विकास की गाथा के दो सौ वर्ष

■ विशाल तिवारी

भारतीय पत्रकारिता की दो सौ वर्षों की यात्रा याद दिलाती है कि स्वतंत्र प्रेस लोकतंत्र की प्राणशक्ति है। भारत में हिंदी पत्रकारिता ने दो सौ वर्षों में भाषा को समृद्ध किया, साहित्य को जन्म दिया (द्विवेदी युग, सरस्वती पत्रिका) और जन-चेतना का वाहक बनी। भारतीय पत्रकारिता की यात्रा आधुनिक भारत के इतिहास का एक अभिन्न अंग भी है। 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिकी द्वारा बंगाल गजट के प्रकाशन से शुरू हुई यात्रा अब डिजिटल युग तक पहुंच चुकी है। 30 मई 1826 को पंडित जुगल किशोर शुक्ल द्वारा उदंत मार्तंड के प्रकाशन से आरंभ हिन्दी पत्रकारिता हुई गिनती के इस वर्ष दो सौ वर्ष पूरे हो गए हैं। 1826 में उदंत मार्तंड का प्रकाशन हिंदी पत्रकारिता का स्वर्णिम क्षण था। पंडित जुगल किशोर शुक्ल द्वारा कलकत्ता से निकाला गया यह साप्ताहिक समाचारपत्र आम भारतीयों की भाषा में समाचार पहुंचाने वाला पहला माध्यम था।

1857 की क्रांति और दमन का दौर

1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम (जिसे ब्रिटिश 'विद्रोह' कहते थे) में भारतीय भाषा के समाचार पत्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उर्दू और हिंदी के पत्रों ने जनता को संगठित किया। इसके बाद ब्रिटिश सरकार दमनकारी कानून लाई। 1857 के बाद प्रेस रजिस्ट्रेशन अधिनियम (1867) और वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम (1878) जैसे कानूनों ने भारतीय भाषा की पत्रकारिता को कुचलने का प्रयास किया। लॉर्ड लिटन द्वारा लाए गए वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम को 'लाइसेंस राज' कहा जाता था, जिसमें बिना अनुमति के समाचार पत्र नहीं प्रकाशित किए जा सकते थे। ऐसे दमनकारी कानूनों के बावजूद भारतीय पत्रकारिता फली-फूली। केसरी (मराठी) के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक के राष्ट्रवादी विचार फैलते रहे। तिलक को 'लोकमान्य' कहा गया और उन्हें 'राजद्रोह' के आरोप में जेल हुई। बंगाल में अमृत बाजार पत्रिका (1868) शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष द्वारा शुरू हुई, जो बाद में अंग्रेजी में आई और स्वतंत्रता आंदोलन की सशक्त आवाज बनी। जी. सुब्रमण्यम अय्यर द्वारा मद्रास से द हिंदू (1878) निकाला गया और ट्रिब्यून (1881) पंजाब में शुरू हुआ। सरदार दयाल सिंह मजीठिया द्वारा स्थापित ट्रिब्यून पत्र आज भी प्रासंगिक है। इन पत्रों ने न केवल समाचार दिए, बल्कि जनमत का निर्माण भी किया।

स्वतंत्रता संग्राम में पत्रकारिता की भूमिका

20वीं सदी में स्वतंत्रता संग्राम का सबसे प्रभावी हथियार पत्रकारिता बना। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन (1903) आरम्भ किया और फिर भारत लौटकर यंग इंडिया (1919) और हरिजन (1933) पत्र निकला। उनकी पत्रकारिता 'सत्याग्रह की पत्रकारिता' थी अर्थात सत्य, अहिंसा और नैतिकता पर आधारित। लाल-बाल-पाल (लाला लाजपत राय,

बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल) के समय में वंदे मातरम, बंगाली (सुरेंद्रनाथ बनर्जी) जैसे पत्र उभरे। जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड (1938) निकाला तो सुभाष चंद्र बोस के फॉरवर्ड ब्लॉक ने भी पत्रकारिता के माध्यम से क्रांतिकारी विचार फैलाए। 1905 का बंग-भंग आंदोलन, 1919 का रौलट एक्ट, 1920-22 का असहयोग आंदोलन, 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 में हुए भारत छोड़ो आंदोलन में समाचार पत्रों ने जनता को जागृत रखा। ब्रिटिश सरकार ने प्रेस इमरजेंसी पॉवर्स अधिनियम (1931) जैसे कानून लाकर दबाने की कोशिश की। हजारों पत्रकार जेल गए, फिर भी आवाज नहीं रुकी।

लोकतंत्र का चौथा स्तंभ

15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ तो पत्रकारिता के सामने नई चुनौतियां थी। राष्ट्र निर्माण, एकता, विकास जैसी चुनौतियों के बीच संविधान के अनुच्छेद-19(1)(ए) ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी, लेकिन 19(2) में उचित प्रतिबंध भी लगाए गए। 1950 के दशक में प्रेस कमीशन (1952-54) ने कई सिफारिशें कीं, जिससे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (1966) का गठन हुआ। वर्किंग जर्नलिस्ट्स अधिनियम (1955), डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूजपेपर्स अधिनियम (1954) जैसे कानून भी आए। टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू जैसे अंग्रेजी समाचार पत्र राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हुए। हिंदी में नवभारत टाइम्स, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, राजस्थान पत्रिका आदि उभरे। 1960-70 के दशक में इंदिरा गांधी के समय आपातकाल (1975-77) सबसे बुरा समय था। प्रेस पर प्रतिबन्ध लगाकर कई संपादकों को जेल भेजा गया। इंडियन एक्सप्रेस ने खाली संपादकीय प्रकाशित करके विरोध व्यक्त किया और फिर आपातकाल के बाद प्रेस ने पुनः साहस दिखाया।

आर्थिक उदारीकरण और मीडिया विस्फोट

1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत में मीडिया उद्योग तेजी से बढ़ा। टेलीविजन, केबल, इंटरनेट ने पत्रकारिता को नया रूप दिया और प्रिंट मीडिया में भी बहुरंगी विकास हुआ। क्षेत्रीय भाषाओं के समाचार पत्रों ने ग्रामीण भारत को जोड़ा। 21वीं सदी में डिजिटल क्रांति ने सब बदल दिया। सोशल मीडिया ने नागरिक पत्रकारिता को बढ़ावा दिया, लेकिन गलत एवं भ्रामक समाचार, भड़काऊ टिप्पणियों और ध्रुवीकरण की चुनौतियां भी उत्पन्न की।

चुनौतियां और भविष्य

वर्तमान समय में भारतीय पत्रकारिता कई चुनौतियों का सामना कर रही है। मीडिया हाउसों पर कॉर्पोरेट नियंत्रण, पत्रकारों की सुरक्षा, डेटा प्राइवेसी और एआई का उदय हुआ है और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग सुधार की मांग करती है। फिर भी, आरटीआई, खोजी पत्रकारिता और साहसी रिपोर्टिंग लोकतंत्र को मजबूत कर रही है।

भारतीय पत्रकारिता के दो सौ वर्ष हिकी की साहसिक शुरुआत से लेकर आज के डिजिटल युग तक के संघर्ष की कहानी है। इसने सती प्रथा, बाल विवाह जैसे कुरीतियों को चुनौती दी, स्वतंत्रता दिलाई, लोकतंत्र की रखवाली की और विकास की कहानी सुनाई। दो सौ वर्षों की यह यात्रा याद दिलाती है कि लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र प्रेस प्राण स्वरूप है और पत्रकारिता मात्र व्यवसाय नहीं, एक मिशन है। ■

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।)

सुधी पाठकों !

शिक्षा क्षेत्र की प्रतिनिधि पत्रिका के रूप में 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' मई-2026 अंक आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। यह अंक महत्वूर्ण लेख एवं विभिन्न समसामयिक घटनाक्रमों एवं खबरों को समाहित किए हुए हैं। आशा है, यह अंक आपके आवश्यकताओं के अनुरूप उपादेय साबित होगा। कृपया 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' से संबंधित अपने सुझाव एवं विचार हमें नीचे दिए गए संपादकीय कार्यालय के पते अथवा ई-मेल पर अवश्य भेजें : -

'राष्ट्रीय छात्रशक्ति'
26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,
नई दिल्ली-110002
फोन : 011-23216298
www.chhatrashakti.in
rashtriyachhatrashakti.abvp@gmail.com
www.facebook.com/Rchhatrashakti
www.twitter.com/Rchhatrashakti
www.instagram.com/ Rchhatrashakti

साधारण से असाधारण बनने की यात्रा

■ डा. मूलचंद्र सिंह

'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ' के कार्य का आधार 'स्वयंसेवक' है। संघ में स्वयंसेवक वह है, जिसने शाखा में जाकर परम पवित्र भगवा ध्वज को प्रणाम किया है। स्वयंसेवक के गुणों को 'स्वयंसेवकत्व' कहते हैं, जिसमें राष्ट्र प्रथम के भाव से अपने हर कार्य को राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाने के उद्देश्य से करता है, जो समरस समाज की रचना के लिए प्रयत्नरत रहता है।

स्वयंसेवक की मूल अवधारणा

सामान्यतः स्वयंसेवक को ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जाता हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के समाज के लिए कार्य करता है। लेकिन वास्तव में स्वयंसेवक होना केवल सेवा करना नहीं, बल्कि एक संपूर्ण जीवन दृष्टि को अपनाना है। यह व्यक्ति के विचार, व्यवहार, चरित्र और जीवन के उद्देश्य को निर्धारित करता है।

'स्वयंसेवक' का अर्थ है-'स्वेच्छा से सेवा करने वाला व्यक्ति'। इसमें दो प्रमुख तत्व हैं-स्वेच्छा (voluntariness) और सेवा (service)। अर्थ यह है कि स्वयंसेवक किसी प्रसिद्धि या लाभ के लिए नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक प्रेरणा से कार्य करता है। सेवा को प्रायः दान या सहायता तक सीमित समझ लिया जाता है, लेकिन स्वयंसेवक के लिए सेवा का अर्थ इससे कहीं अधिक व्यापक होता है। सेवा का वास्तविक स्वरूप निःस्वार्थ होता है। इसमें समस्या के समाधान में संलग्न होना, समाज में जागरूकता लाना, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के क्षेत्र में योगदान देना, सामाजिक समरसता और एकता को बढ़ावा देना आदि आता है ।

1934 में डा. केशव बलिराम हेडगेवार और महात्मा गांधी की भेंट के समय भी डा. हेडगेवार ने स्वयंसेवक की अपनी संकल्पना को उनके समक्ष रखा था। वह कहते हैं-'देश की सर्वांगीण उन्नति के लिए आत्मीयता से अपना सार-सर्वस्व अर्पण करने के लिए सिद्ध नेता को स्वयंसेवक समझते हैं तथा संघ का लक्ष्य इस प्रकार के स्वयंसेवकों के निर्माण का है। इस संगठन में स्वयंसेवक और नेता, यह भेद नहीं है। सभी स्वयंसेवक हैं-यह जानकर ही एक-दूसरे को समान समझते हैं तथा सबसे समान रूप से प्रेम करते हैं। किसी प्रकार के भेद को प्रश्रय नहीं देते। इतने थोड़े समय में धन तथा अन्य साधनों का आधार न होते हुए भी संघ-कार्य की इतनी वृद्धि का यही रहस्य है।'

स्वयंसेवक का जीवन 'मैं' से 'हम' की ओर यात्रा है।

वह अपने व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर समाज और राष्ट्र के हित को प्राथमिकता देता है।

चरित्र निर्माण है स्वयंसेवकत्व का आधार

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को व्यक्ति निर्माण की सिद्ध प्रयोगशाला कहा जाता है। यह व्यक्ति निर्माण स्वयंसेवकत्व के धारण करने की अवस्था है। एक सच्चा स्वयंसेवक बनने के लिए सबसे पहले 'स्वयं का निर्माण' आवश्यक है। यदि व्यक्ति का चरित्र मजबूत नहीं है, तो वह समाज में स्थायी प्रभाव नहीं छोड़ सकता। संघ गीत में एक पंक्ति आती है- 'जो चरित्रवान है, वो सदा महान है'। अतः चरित्र निर्माण का कार्य निरंतर अभ्यास से ही संभव है। स्वयंसेवक में कुछ गुण अपेक्षित हैं। इनमें अनुशासन (समय का पालन और नियमितता), विश्वसनीयता (सुसंगतता, स्थिरता, विश्वास), शुचिता (ईमानदारी, सत्यवादिता), सत्यनिष्ठा (प्रामाणिकता, संपूर्णता), आत्मसंयम (इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण), विनम्रता (अहंकार से दूर रहना), समर्पण (कार्य के प्रति पूर्ण निष्ठा) आदि प्रमुख हैं। यह सभी गुण केवल सैद्धांतिक नहीं, बल्कि सहज व्यवहार का हिस्सा हैं।

स्वयंसेवक की कार्यशैली

संगठन सर्वोच्चता और सामूहिक निर्णय का पालन : संगठन व्यक्ति के व्यक्तित्व को विकसित करने का माध्यम बनता है और समाज में एकता स्थापित करता है। संगठन उसे दिशा, प्रेरणा और सहयोग प्रदान करता है। स्वयंसेवक 'मैं' नहीं, 'हम' की भावना से कार्य करता है, वह टीमवर्क और सहयोग को महत्व देता है, सामूहिक प्रयास से बड़े लक्ष्य सहजता से प्राप्त करता है।

व्यवहार और आचरण की महत्ता : स्वयंसेवक के लिए केवल विचार ही नहीं, बल्कि उसका आचरण भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। उसका व्यवहार सरल और सौम्य होता है, वह सभी के साथ समानता का व्यवहार करता है, विवाद से दूर रहकर संवाद को बढ़ावा देता है, लोग स्वयंसेवक को उसके शब्दों से अधिक उसके व्यवहार से पहचानते हैं। इसलिए उसका जीवन ही उसका संदेश बन जाता है।

समाज के प्रति उत्तरदायित्व : स्वयंसेवक अपने समाज के प्रति उत्तरदायी होता है। वह समाज की समस्याओं को समझता है और उनके समाधान के लिए प्रयास करता है। वर्तमान समय में समाज कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसी स्थिति में स्वयंसेवक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि वह समाज में सकारात्मक परिवर्तन का माध्यम बनता है।

विश्वास निर्माण और नेतृत्व विकास : स्वयंसेवक का एक महत्वपूर्ण कार्य समाज में विश्वास निर्माण करना है। पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा से विश्वास बढ़ता है, निरंतर संपर्क और संवाद से संबंध मजबूत होते हैं, सेवा के माध्यम से लोगों में विश्वास भरता है। जब समाज स्वयंसेवक पर विश्वास करता है, तो वह स्वाभाविक रूप से एक सामाजिक नेतृत्व के रूप में उभरता है।

स्वयंसेवक की चुनौतियां एवं संघर्ष :

एक स्वयंसेवक का मार्ग सरल नहीं होता। उसे कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। समय की सीमितता, व्यक्तिगत और पारिवारिक जिम्मेदारियां, समाज की आलोचना एवं विरोध आदि ऐसी अनंत चुनौतियों से वह निरंतर जूझता है, लेकिन स्वयंसेवक इससे घबराता नहीं है। वह धैर्य, सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास के माध्यम से आगे बढ़ता जाता है। वह सादगी और संयम का पालन करके अपने आचरण से उच्च आदर्श स्थापित करता है। यही संघर्ष दूसरों को लिए प्रेरणा बनता है तथा समाज में नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देता है।

व्यक्ति नहीं, एक विचार है स्वयंसेवक : एक ऐसी सोच जो सेवा, समर्पण और नैतिकता पर आधारित है। यह सोच व्यक्ति को अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज और राष्ट्र के लिए कार्य करने की प्रेरणा देती है। एक सच्चा स्वयंसेवक वही है, जो बिना किसी अपेक्षा के, निष्ठा और प्रेम से समाज की सेवा करता है और राष्ट्र प्रथम की भावना से अपने जीवन को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करता है।

अंततः यह कहा जा सकता है कि स्वयंसेवकत्व एक सतत साधना है, एक ऐसी यात्रा-जो व्यक्ति को 'साधारण' से 'असाधारण' बनाती है। यही 'स्वयंसेवक' राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य का आधार है। इसीलिए श्री गुरुजी ने भी कहा है कि यदि कोई मुझे पूछे कि 'तुम्हारे जीवन में सर्वाधिक गर्व करने योग्य कौन सी बात तुम्हें लगती है? तो मैं कहना चाहूंगा कि 'मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं। इससे अधिक गर्व करने योग्य कोई बात नहीं है। ■

(लेखक मोतीलाल नेहरू कालेज, दिल्ली में सहायक प्राध्यापक हैं।)

अभिवाचन कार्यक्रम की झलकियां

RNI NO.: DELBIL/2017/73636
DATE OF POSTING: 10-11 MAY, 2026
DATE OF PUBLISHING: 8 MAY, 2026

POST OFFICE: NDGPO, NEW DELHI
POSTING REGISTRATION NO. DL(C)-11/1409/2024-26

अभिवाचन कार्यक्रम की झलकियां

नागपुर

नागपुर